

NOW NOIDA

Volume - 03 | Issue - 09
September 2026 | Price : ₹ 10/-

RNI: UPHIN/2024/90046

अपडेट

2026



MR. KOTARO NAGASAKI
GOVERNOR OF YAMANASHI PREFECTURE

SHRI YOGI ADITYANATH
CHIEF MINISTER, UTTAR PRADESH



UP-JAPAN INVESTMENT MEET 2026

NOW NOIDA UPDATE

MAGAZINE

Noida की हर खबर, अब आपके साथ

NOW NOIDA UPDATE मैगज़ीन

अपने बिज़नेस को दें
Noida में पहचान!



LOCAL NEWS
UPDATES



BUSINESS
PROMOTION



EVENTS &
LIFESTYLE



REAL ESTATE &
OPPORTUNITIES

ADVERTISEMENT SIZE		RATE (रुपये में)
Full Page	(8.5" x 11")	₹ 70,000
Half Page	(8.5" x 5.5")	₹ 40,000
Quarter Page	(4.25" x 5.5")	₹ 24,000
Front Inside Cover		₹ 1,00,000
Back Cover		₹ 1,20,000
Double Spread	(17" x 11")	₹ 1,40,000



BOOK YOUR AD TODAY!

SPECIAL OFFER!

EXTRA DISCOUNT
ON MULTIPLE
INSERTION BOOKINGS!



9891114598
7428827715



Email: info@nownoida.com
mukesh.mishra@nowuttarpradesh.com



www.nownoida.com

NOW Noida अपडेट सत्य से साक्षात्कार

EDITORIAL TEAM

Editor
Sandeep Kumar Ojha

Managing Editor
Mukesh Mishra

Noida Bureau
Sazid Ali & Nirmal Gaur

Senior Correspondent
Abhishek Pandey & Rishabh Chhabra

Layout Design
Talib Choudhary

Legal Advisor
Md. Shahid, Lawyer

Managing Director
Sandeep Ojha

Director & Publication
MBI DIGITAL PVT. LTD.

Registered Office
Plot No. 99, Ecotech-03, Udhog
Kendra-2, Greater Noida – 201306

Printer & Publisher :
MBI DIGITAL PVT. LTD. Plot No. 99,
Ecotech-03, Udhog Kendra-2,
Greater Noida – 201306
Mobile No. 7428827715, 9220407108
Email : infonownoida@gmail.com
mukesh.mishra@nowuttarpradesh.com

Published by Sandeep Kumar Ojha, Printer and
Publisher for MBI Digital Pvt. Ltd., from Plot No. 99,
Ecotech-3, Udhog Kendra-2, Greater Noida
(Gautambudh Nagar), and printed at
Chandra Prabhu Offset Printing Works Pvt. Ltd.
Plot No. 69, Ecotech-12, Greater Noida,
Uttar Pradesh – 201318. Editor: Sandeep Kumar Ojha
(RNI: UPHIN/2024/90046).

content

Volume – 3 | Issue – 9 | September 2026 | Price : ₹10

उत्तर प्रदेश चुनाव 2027

05

2027 की जंग में
निर्णायक बन सकती हैं
ये 10 सीटें, कुछ सौ वोटों
पर टिका था पूरा खेल
बूथ प्रबंधन और स्थानीय
मुद्दे बनेंगे हथियार

मिलावटखोरों पर लगाम

06

नोएडा में 100 किलो रसगुल्ले
प्रदूषित अवस्था में पाए गए
350 किलो मिलावटी
पनीर किया गया नष्ट, खाद्य
विभाग टीम की बड़ी कार्रवाई

किसानों को बड़ा तोहफा

08

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने
मुआवजा दर में 55.5% की भारी
बढ़ोतरी वहीं यमुना प्राधिकरण
ने बढ़ाई जमीन की मुआवजा दर

कवर स्टोरी: यूपी-जापान साझेदारी

10

यूपी-जापान निवेश सम्मेलन
2026 निवेश की नई कहानी
यमुना सिटी में 'जापानी सिटी'
का रास्ता साफ, ऑटोमोबाइल
और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में
हजारों रोजगार के अवसर

रक्षाबंधन पर विशेष

15

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
ने लखनऊ मनाया रक्षाबंधन
बच्चियों से बंधवाई राखी और
ली सेल्फी 'सकारात्मक सोच
विकसित करें'

YEIDA की प्लॉट स्कीम

22

नोएडा एयरपोर्ट के पास घर
का सपना होगा आसान, 2 नई
रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम पर
नजर, नवरात्रि में लॉन्च की
तैयारी

नेपाल में जलप्रलय

25

नेपाल में भीषण बाढ़ ने बड़े
पैमाने पर मचाई तबाही, 600 से
ज्यादा की मौत, 2482 लापता,
320 भारतीयों की तलाश जारी

भारत और श्रीलंका क्रिकेट मैच

29

चोट के बाद ऋषभ पंत की
शानदार वापसी, जड़ा दमदार
अर्धशतक; धोनी का
बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा

नोएडा में EVM-वीवीपैट की FLC

16

निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता
और सुरक्षा पर दिया जोर, विशेषज्ञों
ने अधिकारियों को मशीनों की
जांच का लाइव और हैड्स-ऑन
प्रशिक्षण दिया

घर का बिगड़ा बजट

18

चीनी के बढ़ते दामों की बड़ी
वजह: यूपी में गन्ने से किसानों
का मोहभंग, प्याज का झटका

UGC, आरक्षण और चुनावी सियासत

20

जंतर-मंतर से उठी आवाज
ने बढ़ाई हलचल ! 2027
और 2029 के चुनावों
पर क्या होगा असर

राशिफल: सितंबर 2026

31

सितंबर का महीना कई
राशियों के लिए अवसरों,
प्रगति और सकारात्मक
बदलाव लेकर आ रहा है
जानिए आपकी राशि के
लिए यह महीना कैसा रहेगा



सम्पादकीय...

Sandeep

संदीप ओझा
संपादक

www.nownoida.com



चीनी की मिठास पर महंगाई और सियासत की कड़वाहट

त्योहारों का मौसम आम आदमी के लिए खुशियों, मेल-मिलाप और मिठास का समय होता है। लेकिन इस बार रसोई में रखी चीनी ने इन खुशियों के बजट का हिसाब बिगाड़ दिया है। देश के कई हिस्सों में चीनी की खुदरा कीमतें 65 से 67 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचना केवल महंगाई का आंकड़ा नहीं, बल्कि उस आर्थिक दबाव का संकेत है जिसका सीधा असर मध्यम वर्ग, गरीब परिवारों, छोटे दुकानदारों और मिठाई कारोबारियों पर पड़ता है। जब रोजमर्रा की जरूरत की वस्तु महंगी होती है तो उसका असर केवल रसोई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे घरेलू बजट पर दिखाई देता है। चीनी की कीमतों में पिछले कुछ समय में आई तेज बढ़ोतरी ने आर्थिक चिंता के साथ-साथ राजनीतिक तापमान भी बढ़ा दिया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल होने के साथ-साथ दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता भी है। ऐसे में घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमत दोनों ही सरकार के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां लाखों किसान और बड़ी संख्या में चीनी मिलें इस पूरे उद्योग से जुड़ी हैं।

कीमतों के पीछे कौन—मौसम, नीति या बाजार?

चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच विपक्ष ने केंद्र सरकार की एथेनॉल नीति और चीनी के डायवर्जन को कठघरे में खड़ा किया है। विपक्ष का सवाल सीधा है—जब भारत चीनी उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में है तो घरेलू बाजार में स्टॉक वर्षों के निचले स्तर तक कैसे पहुंच गया? कांग्रेस सहित कई विपक्षी नेताओं का आरोप है कि गन्ने के रस और चीनी उत्पादन के एक हिस्से को एथेनॉल की ओर मोड़ने की नीति ने घरेलू बाजार में उपलब्ध चीनी की मात्रा को प्रभावित किया है। दूसरी तरफ सरकार इस तर्क को स्वीकार नहीं करती। सरकार के मुताबिक मौजूदा संकट के पीछे केवल एथेनॉल नीति को जिम्मेदार ठहराना वास्तविक स्थिति को सरल बनाना होगा। अल नीनो के प्रभाव से जल संकट, मौसम में बदलाव, गन्ने में लाल सड़न जैसी बीमारियां और उत्पादन में कमी भी कीमतों में बढ़ोतरी के महत्वपूर्ण कारण हैं। यानी सवाल केवल नीति का नहीं, बल्कि उत्पादन, मौसम, मांग और बाजार प्रबंधन के बीच संतुलन का है। यही वह बिंदु है जहां आर्थिक फैसला धीरे-धीरे राजनीतिक बहस में बदल जाता है।

आयात का फैसला और चुनावी राजनीति

कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने करीब एक दशक में पहली

बार 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति दी है। इसके साथ ही जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट जैसे कदम भी उठाए गए हैं। सरकार का तर्क है कि बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि त्योहारी मांग के दौरान उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। लेकिन इस फैसले की राजनीतिक कीमत भी है। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव करीब हैं और चीनी केवल एक खाद्य वस्तु नहीं, बल्कि किसानों, मिल मालिकों, मजदूरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। चीनी की कीमत कम करने की कोशिश जहां उपभोक्ता को राहत दे सकती है, वहीं गन्ना किसानों और चीनी मिलों के हितों के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। विशेषज्ञों की चिंता यही है कि यदि चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बाजार में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया जाता है, तो आने वाले 2026-27 के गन्ना पेराई सीजन में किसानों के भुगतान और मिलों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। यानी आज की राहत और कल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन साधना आसान नहीं होगा।

असली कसौटी आम आदमी की रसोई

चीनी की कीमतों पर जारी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम उपभोक्ता को राहत कब और कितनी मिलेगी? महंगाई की राजनीति में आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रसोई का अनुभव उससे भी ज्यादा निर्णायक होता है। सरकार के सामने एक तरफ उपभोक्ता कीमतों को नियंत्रित करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ गन्ना किसानों की आय, चीनी मिलों की आर्थिक सेहत और एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र के लक्ष्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। विपक्ष के सामने भी केवल आरोप लगाने के बजाय यह बताने की चुनौती है कि वह इस जटिल संतुलन को कैसे साधेगा।

चीनी की मौजूदा कीमतें हमें एक बड़ी आर्थिक सच्चाई याद दिलाती हैं—कृषि नीति, ऊर्जा नीति, बाजार नीति और चुनावी राजनीति एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। गन्ने के खेत से लेकर चीनी की दुकान तक हर फैसला किसी न किसी रूप में आम आदमी की जेब को प्रभावित करता है। त्योहारों के बीच देश को ऐसी राजनीति की जरूरत है जो चीनी की कीमतों को लेकर शोर से आगे बढ़े और समाधान पर बात करे। क्योंकि जनता को राजनीतिक बयानबाजी की मिठास नहीं, अपनी रसोई के बजट में वास्तविक राहत चाहिए। यही सरकार की नीति की भी असली परीक्षा होगी और विपक्ष की राजनीति की भी।



उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर बड़े नेताओं, बड़ी रैलियों और बड़े नारों की चर्चा होती है, लेकिन चुनावी नतीजे कई बार उन सीटों पर तय होते हैं जहां जीत और हार के बीच का अंतर बेहद मामूली होता है। 2022 विधानसभा चुनाव में ऐसी कई सीटें सामने आईं, जहां कुछ सौ वोटों ने विधायक का भविष्य तय कर दिया। धामपुर में 203 वोट, कुर्सी में 217 वोट और चांदपुर में 234 वोटों का अंतर यह बताने के लिए काफी है कि यूपी की राजनीति में एक बूथ और एक मोहल्ला भी पूरी तस्वीर बदल सकता है। अब जब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो इन्हीं करीबी मुकाबले वाली सीटों पर राजनीतिक दलों की नजर सबसे ज्यादा टिकी हुई है। क्योंकि चुनावी रणनीतिकार जानते हैं कि सत्ता की चाबी कई बार ऐसे ही छोटे अंतर वाली सीटों में छिपी होती है।

2022 के आंकड़े क्यों बने रणनीति का आधार

धामपुर, कुर्सी, चांदपुर, नहतौर, रामनगर, इसौली, बिलासपुर, बड़ौत, नकुड़ और कटरा जैसी सीटों के नतीजों ने राजनीतिक दलों को बड़ा संदेश दिया था। इन सीटों पर लाखों मतदाताओं के बीच मुकाबला कुछ सौ वोटों पर सिमट गया था। यही कारण है कि 2027 के लिए तैयार हो रही चुनावी रणनीतियों में इन सीटों का विशेष महत्व है। राजनीतिक दल अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन कारणों से इतने करीबी मुकाबले बने थे। कहीं स्थानीय मुद्दों ने असर डाला, कहीं उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि निर्णायक बनी और कहीं जातीय समीकरणों ने अंतिम समय में परिणाम बदल दिया। इसलिए इन सीटों के पुराने मतदान पैटर्न, बूथवार आंकड़ों और सामाजिक संरचना का गहन अध्ययन किया जा रहा है।

बीजेपी और सपा दोनों के लिए बड़ी परीक्षा

इन 10 सीटों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि 2022 में इनमें से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं, जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को सफलता

मिली थी। एक सीट पर भी मुकाबला बेहद करीबी रहा था। इसका सीधा मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में किसी भी दल की पकड़ पूरी तरह मजबूत नहीं मानी जा सकती। बीजेपी जहां अपने मौजूदा आधार को बचाने की कोशिश करेगी, वहीं समाजवादी पार्टी इन्हें वापसी का बड़ा अवसर मान रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक माहौल ने भी इन सीटों की अहमियत बढ़ा दी है। अगर विपक्ष इन क्षेत्रों में कुछ प्रतिशत वोटों का अतिरिक्त समर्थन हासिल कर लेता है तो परिणाम बदल सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी बूथ प्रबंधन और संगठन की ताकत के भरोसे इन सीटों को बचाने की रणनीति पर काम कर रही है।

बूथ प्रबंधन और स्थानीय मुद्दे बनेंगे हथियार

2027 के चुनाव में इन सीटों पर जातीय समीकरणों के साथ-साथ स्थानीय मुद्दों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, कानून व्यवस्था और किसानों से जुड़े सवाल यहां के मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक दलों ने अभी से बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां तेज करनी शुरू कर दी हैं। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है और मतदाताओं तक सीधा पहुंचने की कोशिश हो रही है। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि जिन सीटों पर जीत का अंतर 500 वोट से भी कम रहा हो, वहां एक मजबूत बूथ नेटवर्क ही सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। यही वजह है कि सभी दल इन क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने और स्थानीय नेताओं को ज्यादा जिम्मेदारी देने पर जोर दे रहे हैं।

2027 की सत्ता का रास्ता यहीं से गुजर सकता है

उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का गणित सिर्फ बड़ी सीटों से नहीं बल्कि ऐसी दर्जनों करीबी सीटों से भी तय होता है। अगर 2022 में इन सीटों के परिणाम उलट जाते तो विधानसभा की तस्वीर भी कुछ अलग हो सकती थी। यही कारण है कि 2027 का चुनाव नजदीक आते ही इन सीटों का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ने लगा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल जानते हैं कि कुछ सौ वोटों का अंतर सरकार और विपक्ष के बीच की दूरी तय कर सकता है। इसलिए आने वाले महीनों में इन सीटों पर सबसे ज्यादा राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल इतना तय है कि 2027 की चुनावी लड़ाई में यूपी की ये 10 सीटें सिर्फ विधानसभा क्षेत्र नहीं रहेंगी, बल्कि सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा और राजनीतिक दलों की असली ताकत का पैमाना बनेंगी।



गौ तमबुद्धनगर में मिलावटखोरी पर कार्रवाई, 100 किलो रसगुल्ले नष्ट नोएडा। त्योहारों के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सेक्टर-72 स्थित सरफाबाद में एक रसगुल्ला निर्माणशाला पर कार्रवाई करते हुए करीब 100 किलोग्राम रसगुल्ले नष्ट कराए। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान रसगुल्ले प्रदूषित अवस्था में

सरफाबाद की रसगुल्ला निर्माणशाला में मिली खामियां

खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल गुप्ता और रितु सक्सेना की टीम ने सरफाबाद, सेक्टर-72 स्थित प्रदीप कुमार की रसगुल्ला निर्माणशाला का निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य पदार्थ की स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई। अधिकारियों ने रसगुल्ले का नमूना जांच के लिए संग्रहित किया। वहीं, दूषित अवस्था में रखे करीब 100 किलोग्राम रसगुल्लों को मौके पर ही नष्ट कराया गया। विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे खाद्य पदार्थों को उपभोक्ताओं तक पहुंचने से रोकना है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।



पाए गए और उन पर मक्खियां एवं मच्छर पड़े हुए थे। अधिकारियों ने मौके से रसगुल्ले का एक नमूना लिया। इसके बाद शेष करीब 100 किलोग्राम रसगुल्लों को नष्ट करा दिया गया, ताकि इन्हें बाजार में बिक्री के लिए न भेजा जा सके।





अलीगढ़ से सप्लाई के लिए लाई गई पनीर की खेप जांच में गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी, खाद्य विभाग ने नमूने जांच के लिए भेजे

ग्रेटर नोएडा। खाद्य पदार्थों में मिलावट और खराब गुणवत्ता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ग्रेटर नोएडा में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने अलीगढ़ से ग्रेटर नोएडा में सप्लाई के लिए लाई जा रही पनीर की एक खेप को जांच के दौरान पकड़ा। गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने के बाद करीब 350 किलोग्राम पनीर को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं की सेहत से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच जारी रहेगी।

अलीगढ़ से ग्रेटर नोएडा पहुंची थी पनीर की खेप

खाद्य विभाग की टीम ने जांच अभियान के दौरान पनीर से भरी गाड़ी को रोककर उसमें रखी खाद्य सामग्री की जांच की। अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में पनीर की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। इसके बाद टीम ने लगभग 350 किलो पनीर को मौके पर नष्ट करा दिया, ताकि खराब गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ बाजार में पहुंचकर लोगों की सेहत को प्रभावित न कर सके। विभाग की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब बाजार में दूध और उससे बने उत्पादों की मांग लगातार बनी रहती है। पनीर जैसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं की चिंता भी लगातार बढ़ती रही है।

नमूने प्रयोगशाला भेजे, रिपोर्ट से स्पष्ट होगी स्थिति

कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पनीर के नमूने भी लिए हैं। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि पनीर में किस स्तर की गुणवत्ता संबंधी कमी या किसी प्रकार की मिलावट थी। यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मौके पर पनीर को नष्ट किए जाने के बावजूद अंतिम निष्कर्ष प्रयोगशाला जांच के बाद ही सामने आएगा। इसलिए फिलहाल इसे खराब गुणवत्ता वाला पाए गए पनीर की खेप के रूप में देखा जा रहा है और अंतिम स्थिति जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।

मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक खाद्य आयुक्त नोएडा के सर्वेश कुमार ने कहा है कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विश्लेषण: जांच से ज्यादा जरूरी है सप्लाई चेन की निगरानी ग्रेटर नोएडा में पकड़ी गई पनीर की खेप यह सवाल भी खड़ा करती है कि खाद्य पदार्थ शहर के बाजारों तक पहुंचने से पहले कितने स्तर की जांच से गुजरते हैं। अलीगढ़ से पनीर की खेप ग्रेटर नोएडा पहुंची, ऐसे में उत्पादन स्थल से लेकर परिवहन और स्थानीय सप्लाई तक पूरी श्रृंखला की निगरानी महत्वपूर्ण हो जाती है। पनीर जैसे जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों में तापमान नियंत्रण, स्वच्छता और भंडारण की स्थिति भी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए केवल बाजार में पहुंचने के बाद जांच करने के बजाय उत्पादन और परिवहन स्तर पर भी नियमित निगरानी जरूरी है। वहीं, प्रयोगशाला रिपोर्ट इस कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। रिपोर्ट से यह तय होगा कि पनीर में वास्तविक मिलावट थी या उसकी गुणवत्ता किसी अन्य वजह से निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी।

उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी सावधानी

खाद्य विभाग की कार्रवाई के बीच उपभोक्ताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पनीर और अन्य दुग्ध उत्पाद खरीदते समय पैकेजिंग, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और लाइसेंस संबंधी जानकारी देखना जरूरी है। संदिग्ध गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ की शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंचाना भी उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है।

निष्कर्ष

ग्रेटर नोएडा में करीब 350 किलो पनीर नष्ट किए जाने की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सख्ती का संकेत है। हालांकि पनीर की वास्तविक गुणवत्ता और उसमें किसी प्रकार की मिलावट की स्थिति प्रयोगशाला जांच की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में रिपोर्ट और विभाग की आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण होगी।





नोएडा-बुलंदशहर के किसानों की बल्ले-बल्ले यमुना प्राधिकरण ने बढ़ाई जमीन की मुभावजा दर

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 92वीं बोर्ड बैठक में क्षेत्र के विकास, औद्योगिक निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी को लेकर कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय किसानों से भूमि खरीद की दर बढ़ाने का रहा। प्राधिकरण ने किसानों की सहमति से भूमि खरीद की मौजूदा दर में करीब छह प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इससे नोएडा, बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्र में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने वाले किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। 31 जुलाई 2026 तक प्राधिकरण की आय 1853.74 करोड़ रुपये पहुंच गई है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में यह करीब 90.25 प्रतिशत अधिक है। आय में यह वृद्धि इस बात का संकेत देती है कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विकास और निवेश गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं।

किसानों को जमीन के बदले मिलेगा ज्यादा मुआवजा

प्राधिकरण पहले किसानों से भूमि 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से खरीद रहा था। अब इस दर को करीब छह प्रतिशत बढ़ाकर 4558 रुपये प्रति वर्गमीटर करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, दूसरे विकल्प के तहत किसानों को 4037 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर के साथ सात प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ भी दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और खरीद से जुड़े मामलों में किसानों की सहमति को प्राथमिकता देने का यह फैसला क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक स्वीकार्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

500 एकड़ में बनेगा मेडिकल हब

सेक्टर-13 में 500 एकड़ क्षेत्रफल में मेडिकल हब विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा उद्योग को एक ही क्षेत्र में बढ़ावा देना है। मेडिकल हब विकसित होने के बाद अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा संस्थान और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी औद्योगिक गतिविधियों के लिए नया इकोसिस्टम तैयार होने की उम्मीद है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।

यूनिवर्सिटी टाउनशिप से शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा

सेक्टर-14 में 480 एकड़ में यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएगी। इस परियोजना से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों के लिए क्षेत्र में निवेश का रास्ता खुल सकता है। एयरपोर्ट के आसपास शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्रों का एक साथ विकास होने से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को भविष्य के एक बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना को मजबूती मिलेगी।

ताइवान सिटी और फार्मा क्लस्टर से बढ़ेगा औद्योगिक निवेश

सेक्टर-06 में 300 एकड़ में ताइवान सिटी विकसित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसका फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और निवेशकों के लिए क्षेत्र में औद्योगिक आधार तैयार होने की उम्मीद है। इसी सेक्टर में 100 से 125 एकड़ में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। यहां GMP मानकों के अनुरूप दवा निर्माण इकाइयां स्थापित करने की योजना है। इससे दवा उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

मेडिकल डिवाइस पार्क में मिलेगी टेस्टिंग सुविधा

मेडिकल डिवाइस पार्क में अंतरराष्ट्रीय स्तर की मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय भी अहम है। इससे भारतीय कंपनियों को अपने उत्पादों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए विदेश जाने की आवश्यकता कम होगी। इस सुविधा से कंपनियों के समय और लागत दोनों की बचत हो सकती है। साथ ही भारत में मेडिकल डिवाइस निर्माण के क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद मिलेगी।

एयरपोर्ट कनेक्टिविटी होगी और मजबूत

सेक्टर-23बी में अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा विकसित किया जाएगा। इसका सीधा फायदा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले यात्रियों को मिल सकता है। बस अड्डे के माध्यम से स्थानीय और क्षेत्रीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने की योजना है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर हिंडन नदी के ऊपर नया पुल बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे बारिश के दौरान आवागमन बेहतर होने और आसपास के लोगों को सुरक्षित संपर्क मार्ग मिलने की उम्मीद है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड का किसानों को बड़ा तोहफा, मुआवजा दर में 55.5% की भारी बढ़ोतरी



सुनील कुमार सिंह
AGEO, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा के विकास में किसानों की भूमिका और योगदान को देखते हुए प्राधिकरण बोर्ड ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। शासन के निर्देश पर हुई बोर्ड बैठक में किसानों से जमीन खरीदने के लिए मुआवजा दर को 4125 रुपये से बढ़ाकर 6415 रुपये प्रति वर्गमीटर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मौजूदा दर के मुकाबले यह 55.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इस फैसले को किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी एकमुश्त मुआवजा वृद्धि माना जा रहा है। मौजूदा दर में सीधे 2290 रुपये प्रति वर्गमीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, 6 प्रतिशत आबादी भूखंड का विकल्प लेने वाले किसानों को 5725 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा दिया जाएगा।

10 साल बाद फिर लागू हुआ 6% आबादी भूखंड का प्रावधान

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने किसानों के लिए 6 प्रतिशत आबादी भूखंड देने की व्यवस्था को भी दोबारा लागू करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2016 में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। अब बोर्ड की मंजूरी के बाद इसे फिर शुरू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत आबादी भूखंड लेने वाले किसानों के लिए अलग सेक्टर विकसित किए जाएंगे। इन सेक्टरों को आवासीय, औद्योगिक और बिल्डर क्षेत्रों की तर्ज पर विकसित करने की योजना है।

40 से 2500 वर्गमीटर तक होगा आबादी भूखंड

प्राधिकरण के फैसले के मुताबिक आबादी भूखंड का क्षेत्रफल न्यूनतम 40 वर्गमीटर और अधिकतम 2500 वर्गमीटर होगा। प्रमुख मार्गों से लगी जमीन के किसानों को आबादी भूखंड के आवंटन में चयन की वरीयता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसानों की जमीन पर मौजूद परिसंपत्तियों के लिए भूमि के मुआवजे के अतिरिक्त अलग से भुगतान किया जाएगा। मुआवजे की पूरी राशि पारदर्शी तरीके से किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

जमीन खरीद प्रक्रिया के लिए बनेगा विशेष सेल

किसानों को जमीन की खरीद प्रक्रिया के दौरान होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए एसीईओ की अध्यक्षता में जमीन अधिग्रहण सेल गठित करने के निर्देश दिए

गए हैं। यह सेल जमीन खरीद की प्रक्रिया को पूरा कराने में किसानों की सहायता करेगा। इसका उद्देश्य किसानों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाना और जमीन खरीद की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना है।

2014 से 2026 तक ऐसे बढ़ी मुआवजा दर

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में किसानों से जमीन खरीदने के लिए मुआवजा दर में समय-समय पर बदलाव किया गया है।

वित्तीय वर्ष	मुआवजा दर
2014-15	₹3,500 प्रति वर्गमीटर
2022-23	₹3,750 प्रति वर्गमीटर
2023-24	₹4,125 प्रति वर्गमीटर
2026-27	₹6,415 प्रति वर्गमीटर

वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक मुआवजा दर 3500 रुपये प्रति वर्गमीटर थी। इसके बाद 2022-23 में इसमें 250 रुपये और 2023-24 में 375 रुपये की वृद्धि हुई। लेकिन 2026-27 में सीधे 2290 रुपये प्रति वर्गमीटर की वृद्धि की गई है। किसानों और प्राधिकरण के बीच रिश्ते में महत्वपूर्ण बदलाव

यह फैसला केवल मुआवजा राशि बढ़ाने तक सीमित नहीं है। 6 प्रतिशत आबादी भूखंड का प्रावधान दोबारा लागू होने से किसानों को विकास प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने की कोशिश भी दिखाई देती है। जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही आरक्षण पत्र देने की व्यवस्था किसानों के लिए प्रक्रिया को अधिक निश्चित बनाने में मदद कर सकती है।

मुआवजा वृद्धि का व्यापक असर

मुआवजा दर में 55.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी से किसानों की जमीन की कीमत में बड़ा अंतर आएगा। खासतौर पर उन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा जिनकी जमीन प्राधिकरण भविष्य की विकास परियोजनाओं के लिए खरीदेगा। दूसरी ओर, प्राधिकरण के लिए जमीन खरीद की लागत बढ़ेगी। ऐसे में परियोजनाओं की लागत और भूमि खरीद के बजट पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है।





मुकेश मिश्रा
मैनेजिंग एडिटर

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली के ताज पैलेस में यूपी-जापान निवेश सम्मेलन 2026 का आयोजन कर जापानी निवेशकों के सामने प्रदेश में बदलते औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य की तस्वीर पेश की। सम्मेलन में जापान से आए 200 से अधिक सीईओ, प्रबंध निदेशक, कंटी हेड्स और वरिष्ठ उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भारत और जापान के बीच आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करना रहा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, औद्योगिक पार्क और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि बेहतर कानून-व्यवस्था और निवेशक-अनुकूल नीतियों के साथ यह बुनियादी ढांचा प्रदेश को बड़े वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक बना रहा है। मुख्यमंत्री ने जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश का आमंत्रण देते हुए विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं पर जोर दिया। इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के सेक्टर-5ए में करीब 500 एकड़ में 'जापानी सिटी' विकसित करने की योजना रही। प्रस्तावित परियोजना जापानी उद्योगों, कारोबार और नागरिकों के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय सुविधाओं वाला समर्पित इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।



आदित्यनाथ, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रदेश की निवेश संभावनाओं को सामने रखा।

एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक, यूपी ने दिखाया नया इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल

यमुना सिटी में दो बड़े प्रोजेक्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग

सम्मेलन के दौरान यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं का वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी हुआ। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में

औद्योगिक गतिविधियों के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।



एस्कॉर्ट्स कुबोटा का 2,029 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट

एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड को यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-10 में 154 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। कंपनी करीब 2,029 करोड़ रुपये के निवेश से विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। परियोजना से लगभग 4,000 रोजगार अवसर पैदा होने का अनुमान है। यहां प्रतिवर्ष करीब 60 हजार ट्रैक्टर बनाए जाने की योजना है। इसके साथ ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी से जुड़े विभिन्न कलपुर्जों और घटकों का भी उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना यमुना सिटी को कृषि उपकरण और इंजीनियरिंग विनिर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है।

स्पार्क मिंडा से 6,440 रोजगार का दावा

स्पार्क मिंडा समूह की परियोजनाओं के लिए यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-10 और सेक्टर-24 में भूमि आवंटित की गई है। करीब 1,166 करोड़ रुपये के निवेश वाली इस परियोजना से लगभग 6,440 रोजगार अवसर सृजित होने का अनुमान है। परियोजना में प्रतिवर्ष करीब 20 लाख यूनिट इलेक्ट्रॉनिक स्विच, सेंसर, यूएसबी चार्जर और अन्य ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण की योजना है। इससे उत्तर प्रदेश के ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

विश्लेषण: जापानी निवेश से बदल सकती है यमुना सिटी की औद्योगिक पहचान यूपी-जापान निवेश सम्मेलन को केवल निवेश जुटाने वाले कार्यक्रम के तौर पर देखना पर्याप्त नहीं होगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाएं यह संकेत देती हैं कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास का इलाका धीरे-धीरे मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट आधारित औद्योगिक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। 'जापानी सिटी' की अवधारणा इस बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। यदि जापानी कंपनियों के साथ औद्योगिक निवेश, आवासीय सुविधाएं, व्यापारिक गतिविधियां और कुशल मानव संसाधन एक ही इकोसिस्टम में विकसित होते हैं तो इससे क्षेत्र में निवेश की निरंतरता बढ़ सकती है। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और फ्रेट कनेक्टिविटी के साथ औद्योगिक इकाइयों की नजदीकी कंपनियों की लॉजिस्टिक्स लागत और समय को कम करने में मदद कर सकती है। वहीं एस्कॉर्ट्स कुबोटा और स्पार्क मिंडा जैसे प्रोजेक्ट केवल उत्पादन इकाइयां नहीं हैं, बल्कि इनके आसपास सप्लायर, कंपोनेंट निर्माता, सर्विस प्रोवाइडर और अन्य सहायक उद्योग विकसित होने की संभावना भी बनती है।

चुनौती निवेश को जमीन पर उतारने की

हालांकि निवेश घोषणाओं और ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद असली चुनौती परियोजनाओं को तय समय में धरातल पर उतारने की होगी। बड़े औद्योगिक निवेश के लिए जमीन, बिजली, पानी, कुशल श्रम, लॉजिस्टिक्स और त्वरित प्रशासनिक मंजूरी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर मजबूत सप्लाय चैन जरूरी होती है। यदि



सरकार इन सभी क्षेत्रों में निरंतर सहयोग उपलब्ध कराती है तो जापानी निवेश उत्तर प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि का बदलाव ला सकता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर एवं उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों में जापानी निवेश को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को विश्वस्तरीय अवसररचना, कुशल मानव संसाधन तथा त्वरित स्वीकृति प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में दीपक कुमार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC), उत्तर प्रदेश, आलोक कुमार, अध्यक्ष, यमुना प्राधिकरण, राकेश कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना प्राधिकरण तथा शैलेन्द्र कुमार भाटिया, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं नोडल अधिकारी, निवेश प्रकोष्ठ, यमुना प्राधिकरण सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे।



निष्कर्ष

यूपी-जापान निवेश सम्मेलन 2026 ने उत्तर प्रदेश और जापान के बीच आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने की संभावनाएं सामने रखी हैं। 500 एकड़ की जापानी सिटी, एस्कॉर्ट्स कुबोटा और स्पार्क मिंडा की परियोजनाएं तथा हाई-टेक सेक्टर में निवेश का आमंत्रण यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि सम्मेलन में प्रस्तुत निवेश प्रस्ताव कितनी तेजी से उत्पादन इकाइयों में बदलते हैं और इनसे स्थानीय युवाओं, एमएसएमई तथा पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ मिलता है। यदि योजनाएं निर्धारित गति से आगे बढ़ती हैं तो यमुना सिटी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जापानी-औद्योगिक निवेश केंद्रों में शामिल हो सकती है।





जापान के साथ टैलेंट और टेक्नोलॉजी का गठजोड़, गलगोटियास यूनिवर्सिटी में 200 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत

गौ तमबुद्धनगर। भारत और जापान के बीच अकादमिक, तकनीकी और रिसर्च सहयोग को नई ऊंचाई देने की दिशा में गलगोटियास यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण पहल हुई। यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में पहुंचे करीब 200 सदस्यीय उच्चस्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल का यूनिवर्सिटी परिसर में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए अंतरराष्ट्रीय करियर के अवसर बढ़ाने और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान को गति देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण समझौते किए गए। यह पहल ऐसे समय में हुई है जब भारत और जापान के बीच तकनीक, कौशल विकास, स्वच्छ ऊर्जा और मानव संसाधन के क्षेत्र में सहयोग लगातार विस्तार ले रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए भी यह साझेदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे राज्य के युवाओं और उच्च शिक्षा संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने की संभावनाएं मजबूत होती हैं। तकनीकी प्रक्रिया से लेकर सुरक्षा उपायों तक दी जानकारी कार्यशाला के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों ने ईवीएम एवं वीवीपैट की एफएलसी से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों को मशीनों की तकनीकी

जांच के साथ-साथ एफएलसी के दौरान अपनाए जाने वाले प्रशासनिक और सुरक्षा प्रोटोकॉल से भी अवगत कराया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था, एफएलसी प्रक्रिया तथा अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित प्रत्येक प्रक्रिया निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी सावधानी और पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाए।



टैलेंट मोबिलिटी से क्लीन एनर्जी रिसर्च तक साझेदारी

यामानाशी प्रीफेक्चर सरकार के साथ एमओयू और यामानाशी यूनिवर्सिटी के साथ लेटर ऑफ इंटेन्ट (LOI) के माध्यम से दीर्घकालिक सहयोग की नींव रखी गई। इसका दायरा केवल विद्यार्थियों के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि टैलेंट मोबिलिटी, फैकल्टी सहयोग, स्किलिंग और संयुक्त अनुसंधान तक विस्तारित किया गया है। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (JETRO) की प्रस्तुति के दौरान दोनों क्षेत्रों के बीच उद्योग और प्रतिभा साझेदारी को मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के बाद कैपस में अलग-अलग विषयों पर फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन आयोजित किए गए। ग्रीन हाइड्रोजन पर केंद्रित चर्चा में जापानी प्रतिनिधियों और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी सदस्यों ने क्लीन एनर्जी, लो-कार्बन मोबिलिटी,

टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और स्टूडेंट-रिसर्च एक्सचेंज की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। इसी दौरान यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने यूनिवर्सिटी के वातावरण और उपलब्ध सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा, “यदि यह 30 वर्ष पहले होता, तो मैं गलगोटियास यूनिवर्सिटी में अवश्य प्रवेश लेता।”



हेल्थकेयर, एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी दिखी रुचि

जापानी प्रतिनिधिमंडल के एक समूह ने यूनिवर्सिटी के डिजिटल नर्सिंग स्किल्स एंड सिमुलेशन सेंटर का दौरा किया। वहां नर्सिंग और हेल्थ साइंसेज से जुड़े सल में हेल्थकेयर एजुकेशन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से भी बातचीत की। इस दौरान जापानी प्रतिनिधियों ने कैपस लाइफ, भारतीय संस्कृति और विद्यार्थियों की करियर आकांक्षाओं को समझने में रुचि दिखाई। दूसरे समूह ने आईओएस डेवलपमेंट सेंटर, एलएंडटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर से जुड़ी एडवांस्ड लेब्स का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्री-इंटीग्रेटेड टीचिंग और रिसर्च मॉडल को भी समझा।



विद्यार्थियों के लिए खुलेंगे ग्लोबल करियर के रास्ते

गलगोटियास यूनिवर्सिटी के सीईओ डॉ. ध्रुव गलगोटिया ने कहा कि इन समझौतों के जरिए विद्यार्थियों के लिए ग्लोबल करियर के वास्तविक अवसर तैयार होंगे। साथ ही रिसर्चर्स को क्लीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी भविष्य की तकनीकों से जुड़ी चुनौतियों पर जापान के विशेषज्ञों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। कुलाधिपति सुनील गलगोटिया ने भारत-जापान संबंधों को ज्ञान, अनुशासन और पारस्परिक सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने के विजन और उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा से प्रेरित है। दोनों पक्षों ने समझौतों को केवल औपचारिक दस्तावेज तक सीमित न रखते हुए स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी कोलैबोरेशन, स्किलिंग और जॉइंट रिसर्च के ठोस कार्यक्रमों में

बदलने की प्रतिबद्धता जताई।

विश्लेषण: शिक्षा से आगे बढ़कर रोजगार और तकनीक का नेटवर्क भारत-जापान के बीच गलगोटियास यूनिवर्सिटी के माध्यम से हुआ यह सहयोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं रह गए हैं, बल्कि वे उद्योग, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार के लिए प्रतिभा तैयार करने के प्रमुख केंद्र बन रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जापान की विशेषज्ञता



और भारत की युवा प्रतिभा का मेल भविष्य में नए शोध और रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। गौतमबुद्धनगर और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मेडिकल डिवाइस और हाई-टेक मैनुफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकसित हो रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय और जापानी संस्थानों के बीच तकनीकी साझेदारी क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को भी अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती दे सकती है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि स्टूडेंट एक्सचेंज, संयुक्त शोध और स्किलिंग कार्यक्रम नियमित रूप से लागू होते हैं तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ अंतरराष्ट्रीय कार्य संस्कृति और वास्तविक औद्योगिक अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां रहीं मौजूद

कार्यक्रम में यामानाशी के उप-गवर्नर जुनिची इशिदेरा, यामानाशी सरकार के एडवाइजर नीरेंद्र उपाध्याय, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जेवर



विधायक धीरेंद्र सिंह समेत कई प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे।

निष्कर्ष

गलगोटियास यूनिवर्सिटी में यामानाशी के 200 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा भारत-जापान संबंधों को शिक्षा और तकनीक के स्तर पर नई दिशा देने वाली पहल के रूप में सामने आई है। दो महत्वपूर्ण समझौतों के जरिए ग्लोबल करियर, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, हेल्थकेयर और हाई-टेक रिसर्च में सहयोग का रास्ता खुला है। अब इस साझेदारी की असली सफलता इस बात से तय होगी कि एमओयू और LOI कितनी तेजी से ठोस विनिमय, संयुक्त

यूपी-जापान

साझेदारी को नई उड़ान



संदीप भोजरा
संपादक

लखनऊ/ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश और जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के बीच आर्थिक, पर्यटन और रोजगार संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट में तीन महत्वपूर्ण समझौतों यानी एमओयू का आदान-प्रदान हुआ। इन समझौतों से उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जापान में रोजगार के अवसर बढ़ाने, दोनों क्षेत्रों के बीच पर्यटन को प्रोत्साहित करने और जापानी भाषा में दक्ष मानव संसाधन तैयार करने का रास्ता मजबूत हुआ है।

100 से ज्यादा युवाओं को जापान में मिला रोजगार

इन्वेस्ट यूपी और जापान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर (टीटीआरसी) के बीच हुए एमओयू को रोजगार के लिहाज से अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की ओर से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार और जापानी पक्ष से जापान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर सुचकी कमाडा ने समझौते का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में बताया गया कि टीटीआरसी के प्रयासों से अब तक उत्तर प्रदेश के 100 से अधिक युवाओं को जापान में रोजगार मिल चुका है। युवाओं को जापान में प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दोनों पक्षों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

इस अवसर पर जापान में रोजगार हासिल करने वाले उत्तर प्रदेश के दो युवाओं पुष्पेंद्र सिंह चौहान और आदर्श कुमार कुशवाहा को मंच पर बुलाकर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उनकी सफलता को उत्तर प्रदेश और जापान के बीच बढ़ते कौशल एवं रोजगार संबंधों का उदाहरण बताया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने दोनों युवाओं और टीटीआरसी के प्रयासों का तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया।

यूपी और यामानाशी के बीच पर्यटन कनेक्शन मजबूत

दूसरा महत्वपूर्ण एमओयू उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग और जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के बीच हुआ। इसका उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के साथ पर्यटन क्षेत्र में लंबे समय तक प्रभावी और निरंतर सहयोग विकसित करना है। उत्तर प्रदेश की ओर से पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात तथा जापान की ओर से यामानाशी प्रीफेक्चर सरकार के संस्कृति, पर्यटन एवं खेल विभाग के डायरेक्टर जनरल योशी यूकी कोजुमी ने एमओयू का आदान-प्रदान किया। इस समझौते के जरिए दोनों क्षेत्रों के पर्यटन संसाधनों और संभावनाओं को एक-दूसरे के सामने प्रस्तुत करने, पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और पर्यटन से जुड़े संस्थानों के बीच लगातार संवाद को बढ़ावा

देने का आधार तैयार हुआ है।

जापानी भाषा में दक्ष युवाओं की बढ़ेगी मांग

तीसरा एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन विभाग और यामानाशी प्रीफेक्चर के बीच हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य जापानी भाषा में दक्ष वर्कफोर्स की निरंतर आपूर्ति के लिए दोनों पक्षों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश की ओर से श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमके शनमुखा सुंदरम और जापानी पक्ष की ओर से यामानाशी प्रीफेक्चर सरकार के इन्वैशन प्रमोशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कत्सुया हादा ने समझौते का प्रतिनिधित्व किया। समझौते के तहत जापानी भाषा में दक्ष मानव संसाधन तैयार करने और उन्हें जापान में उपलब्ध रोजगार अवसरों से जोड़ने की दिशा में सहयोग बढ़ाया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश के युवाओं को जापान में रोजगार के नए रास्ते मिलने की उम्मीद है। वहीं जापानी कंपनियों के लिए भी प्रशिक्षित और भाषा-दक्ष भारतीय वर्कफोर्स उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यानी यह साझेदारी केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्किल ट्रेनिंग, भाषा शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय रोजगार के बीच एक मजबूत कड़ी बनाने का काम करेगी।

तीन समझौते, सहयोग के तीन बड़े रास्ते

यूपी और यामानाशी के बीच हुए ये तीन एमओयू तीन अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग का आधार तैयार करते हैं। पहला समझौता युवाओं को जापान में प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ता है, दूसरा पर्यटन संबंधों को मजबूत करता है और तीसरा जापानी भाषा में दक्ष मानव संसाधन तैयार करने पर केंद्रित है। आने वाले समय में इन समझौतों के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जापान में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

यूपी-जापान साझेदारी से रोजगार और पर्यटन को नई रफ्तार

3 एमओयू — रोजगार, पर्यटन और कौशल विकास पर सहयोग
100+ युवा — अब तक जापान में रोजगार हासिल कर चुके
यामानाशी — जापान का प्रमुख साझेदार प्रीफेक्चर
जापानी भाषा — रोजगार योग्य वर्कफोर्स तैयार करने पर जोर
पर्यटन — यूपी के आध्यात्मिक, बौद्ध और हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा
यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट में उत्तर प्रदेश और जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के बीच तीन एमओयू हुए। समझौतों से युवाओं के लिए जापान में रोजगार, पर्यटन सहयोग और जापानी भाषा में दक्ष वर्कफोर्स तैयार करने की दिशा में काम बढ़ेगा।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। पांच कालीदास मार्ग पर स्थित आवास पर उन्होंने निराश्रित बच्चियों और छात्राओं से राखी बंधवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चियों को रिटर्न गिफ्ट भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निराश्रित बच्चियों और छात्राओं से राखी बंधवाते समय काफी भावुक भी दिखे। उन्होंने सभी को खूब पढ़ने-लिखने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने बच्चियों से राखी बंधवाने के बाद उनको लिफाफे में उपहार के साथ ही गिफ्ट हैपर भी देकर विदा किया।

बच्चियों के साथ सेल्फी

बच्चों को बेहद प्यार और दुलार देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ बच्चे भी बन जाते हैं। बीते दिनों लखनऊ के दौरे पर आए जापानी बच्चों के साथ सेल्फी लेने वाले योगी आदित्यनाथ ने आज भी बच्चियों के साथ सेल्फी लेकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का उत्सव नहीं, बल्कि कर्तव्य और संरक्षण की भावना का भी पर्व है।

विश्वास और संस्कार का पर्व

सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर प्रदेश के सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर्व स्नेह, विश्वास और संस्कार का पर्व है। सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक बधाई। भाई-बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक इस पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामना। रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का उत्सव नहीं, बल्कि कर्तव्य और संरक्षण की भावना का भी पर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पवित्र पर्व पर हम सब संकल्प लें। सनातन विरासत की मजबूती के साथ ही साथ पारिवारिक मूल्य को मजबूत करने का संकल्प लें। 'सकारात्मक सोच विकसित करें, अच्छे काम के लिए खुद को तैयार करें'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को जीवन में सफलता के लिए सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने भीतर सकारात्मक सोच विकसित करनी होगी और अच्छे कार्यों

के लिए खुद को तैयार करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि व्यक्ति की सोच उसके भविष्य को दिशा देती है। इसलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ रचनात्मक गतिविधियों और अच्छे विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अपनी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को मजबूत बनाए रखने के लिए बच्चों को अच्छी किताबें पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए।

'स्नेहबंधन' में बच्चों ने बांधी राखी

रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित 'स्नेहबंधन' कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधी। सीएम योगी ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें पर्व की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में रक्षाबंधन की आत्मीयता और भाई-बहन के रिश्ते की भावना देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने, सकारात्मक सोच रखने और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया।



ईवीएम-वीवीपैट की एफएलसी को लेकर ग्रेटर नोएडा में बड़ी कार्यशाला, 21 जिलों के अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

गौ तमबुद्धनगर। आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) को लेकर गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तर की जांच को निर्धारित मानकों के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी और प्रशासनिक प्रशिक्षण देना था। कार्यशाला की अध्यक्षता वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग मनीष गर्ग ने की। इसमें उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और एफएलसी सुपरवाइजर्स ने हिस्सा लिया।

**निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता
और सुरक्षा पर दिया जोर,
विशेषज्ञों ने अधिकारियों को
मशीनों की जांच का लाइव और
हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण दिया**

तकनीकी प्रक्रिया से लेकर सुरक्षा उपायों तक दी जानकारी



कार्यशाला के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों ने ईवीएम एवं वीवीपैट की एफएलसी से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों को मशीनों की तकनीकी जांच के साथ-साथ एफएलसी के दौरान अपनाए जाने वाले प्रशासनिक और सुरक्षा प्रोटोकॉल से भी अवगत कराया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था, एफएलसी प्रक्रिया तथा अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों की जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित प्रत्येक प्रक्रिया निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी सावधानी और पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाए।

मशीनों के पूरे जीवन चक्र की दी गई जानकारी

विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को ईवीएम एवं वीवीपैट के संपूर्ण जीवन चक्र से संबंधित प्रशिक्षण दिया। इसमें मशीनों के संचालन से लेकर रैंडमाइजेशन, कमीशनिंग, मतदान प्रक्रिया, मतगणना और मतगणना के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी शामिल रही। ईसीआईएल के विशेषज्ञ पी.सी. मंडल ने ईवीएम एवं वीवीपैट की तकनीकी संरचना और सुरक्षा विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम प्रभाग के सचिव मधुसूदन गुप्ता ने एफएलसी के दौरान सामने आने वाली सामान्य त्रुटियों और उनसे बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों पर जानकारी दी।

केवल प्रेजेंटेशन नहीं, मशीनों पर हुआ हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण

कार्यशाला की खास बात यह रही कि प्रतिभागियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी नहीं दी गई, बल्कि उन्हें वास्तविक ईवीएम और वीवीपैट मशीनों



बीईएल और ईसीआईएल के विशेषज्ञ इंजीनियरों ने मशीनों के संचालन और एफएलसी की प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिकारियों और अन्य प्रतिभागियों को स्वयं मशीनों को संचालित करने और निर्धारित प्रक्रियाओं का अभ्यास कराया गया। इस हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों को मशीनों की तकनीकी और व्यावहारिक कार्यप्रणाली को करीब से समझने का अवसर मिला।

सवाल-जवाब और मूल्यांकन से परखी गई समझ

प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया गया। इसके बाद डाउट-क्लियरिंग सेशन आयोजित कर अधिकारियों के सवालों और जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। सभी प्रतिभागियों से घोषणा-पत्र भी प्राप्त किए गए, जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण में बताए गए विषयों को समझने और किसी प्रकार की शंका शेष नहीं रहने की पुष्टि की।

विश्लेषण: चुनावी प्रक्रिया में एफएलसी क्यों महत्वपूर्ण?

ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग चुनावी प्रक्रिया का एक



महत्वपूर्ण तकनीकी चरण है। इसका उद्देश्य चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की कार्यप्रणाली और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप उनकी तैयारी सुनिश्चित करना है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इस कार्यशाला की खास अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इसमें प्रदेश के 21 जनपदों के अधिकारियों को एक समान प्रक्रिया और प्रोटोकॉल के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इससे अलग-अलग जिलों में एफएलसी के दौरान प्रक्रियात्मक अंतर और संभावित गलतियों को कम करने में मदद मिल सकती है। मशीनों पर लाइव प्रदर्शन और हैंड्स-ऑन अभ्यास अधिकारियों को केवल नियम समझने के बजाय उन्हें व्यवहार में लागू करने का अवसर देता है। वहीं सामान्य त्रुटियों और सावधानियों की जानकारी एफएलसी के दौरान तकनीकी गलतियों की संभावना कम करने में उपयोगी हो सकती है।

पारदर्शिता पर विशेष जोर

कार्यशाला के समापन पर अधिकारियों ने एफएलसी प्रक्रिया को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा करने पर विशेष जोर दिया। निर्देश दिया गया कि ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ी प्रत्येक प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। इसका व्यापक उद्देश्य आगामी विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारु तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियों को मजबूत करना है।

प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद



कार्यशाला में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा, भारत निर्वाचन आयोग के सचिव मधुसूदन गुप्ता, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश अखंड प्रताप सिंह, अपर सचिव भारत निर्वाचन आयोग राकेश कुमार और उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश अमित सिंह समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा 21 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एफएलसी सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, ईसीआईएल के विशेषज्ञ और अन्य संबंधित अधिकारियों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया।

निष्कर्ष



ग्रेटर नोएडा में आयोजित ईवीएम-वीवीपैट एफएलसी कार्यशाला आगामी विधानसभा चुनावों से पहले तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षण में मशीनों की तकनीकी संरचना से लेकर सुरक्षा प्रोटोकॉल, एफएलसी, रैंडमाइजेशन, कमीशनिंग और मतदान के बाद की प्रक्रियाओं तक जानकारी दी गई। अब चुनौती यह होगी कि कार्यशाला में दिए गए प्रशिक्षण और निर्देशों को सभी संबंधित जिलों में उसी गंभीरता और निर्धारित प्रोटोकॉल के साथ लागू किया जाए। चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए तकनीकी दक्षता के साथ पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सबसे महत्वपूर्ण आधार रहेगा।



मक्का-धान की ओर बढ़ा रुझान, तीन साल में गन्ने का रकबा 4% घटा; चीनी उत्पादन में 14% की गिरावट

लखनऊ। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती को लेकर बदलती किसानों की प्राथमिकताएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में गन्ने का रकबा करीब चार प्रतिशत घटा है। इसका सीधा असर चीनी उत्पादन पर पड़ा है और इसी अवधि में चीनी उत्पादन में करीब 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। ऐसे में घरेलू बाजार में बढ़ती मांग और घटते उत्पादन के बीच चीनी की कीमतों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में प्रदेश में गन्ने का कुल रकबा 29.66 लाख हेक्टेयर था। वर्ष 2025-26 में यह घटकर 28.61 लाख हेक्टेयर रह गया। यानी तीन वर्षों में करीब 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र गन्ने की खेती से बाहर हो गया। इसका असर चीनी उत्पादन पर और अधिक दिखाई दिया। 2023-24 में प्रदेश में 104.13 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था, जो 2025-26 में घटकर 89.52 लाख टन रह गया। यानी उत्पादन में 14.61 लाख टन की कमी आई।

रकबा चार फीसदी घटा, उत्पादन में 14 फीसदी की गिरावट



गन्ने के रकबे में चार प्रतिशत की कमी के मुकाबले चीनी उत्पादन में करीब साढ़े तीन गुना अधिक गिरावट कई सवाल खड़े करती है। इसका एक प्रमुख कारण केवल खेती का क्षेत्र कम होना नहीं, बल्कि फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता पर पड़ रहा असर भी है। बीकेटी स्थित चंद्रभानु कृषि महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉ. सत्येंद्र कुमार सिंह के अनुसार मौसम में बदलाव के साथ अगोला बेधक कीट और रेड रॉट बीमारी ने गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। रेड रॉट जैसी बीमारी गन्ने की फसल के लिए गंभीर चुनौती मानी जाती है। यदि समय रहते इसका प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका असर केवल किसानों की उपज पर नहीं, बल्कि चीनी मिलों को मिलने वाले गन्ने की उपलब्धता पर भी पड़ सकता है।

मक्का और धान की ओर क्यों बढ़ रहे किसान?



गन्ने की खेती लंबे समय तक किसानों के लिए प्रमुख नकदी फसल रही है, लेकिन बदलते कृषि समीकरणों में किसान अब दूसरी फसलों की ओर भी रुख कर रहे हैं। मक्का और धान जैसी फसलों को लेकर किसानों का रुझान बढ़ना इसी बदलाव का संकेत है। गन्ने की खेती में लंबा फसल चक्र, लागत, पानी की जरूरत और भुगतान से जुड़ी चिंताएं किसानों के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं बदलते मौसम और रोगों का खतरा भी किसानों के लिए जोखिम बढ़ा रहा है। यदि यह रुझान लंबे समय तक जारी रहता है तो उत्तर

प्रदेश जैसे देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य में चीनी मिलों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

रेड रॉट और मौसम ने बढ़ाई मुश्किल



केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी गन्ना उत्पादन में कमी के पीछे रेड रॉट बीमारी और अल नीनो जैसी मौसमी परिस्थितियों को प्रमुख कारणों में बताया है। उनका कहना है कि मौसम संबंधी प्रभावों ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में कृषि उत्पादन को प्रभावित किया है। यानी मौजूदा चीनी संकट को केवल किसानों के फसल परिवर्तन से जोड़कर देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी। इसमें मौसम, बीमारी, वैश्विक उत्पादन, घरेलू मांग और बाजार की स्थिति सभी की भूमिका है।



त्योहारों से पहले सरकार ने खोला आयात का रास्ता

चीनी की बढ़ती कीमतों और आगामी त्योहारी मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने करीब एक दशक बाद बड़ी मात्रा में चीनी आयात की अनुमति दी है। 20 अगस्त 2026 को टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। यह आयात 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और त्योहारी सीजन में कीमतों पर अतिरिक्त दबाव को रोकना है। रक्षाबंधन, तीज, गणेश उत्सव और अन्य त्योहारों के दौरान मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में चीनी की खपत बढ़ने की संभावना रहती है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार भारत की सालाना चीनी जरूरत करीब 280 लाख टन है और वर्तमान में लगभग 20 से 25 लाख टन का अतिरिक्त स्टॉक उपलब्ध है। इसके बावजूद आने वाले महीनों की मांग को देखते

हुए सरकार ने एहतियाती कदम उठाया है।

ब्राजील से लेकर जमाखोरी तक, कई मोर्चों पर दबाव

चीनी बाजार पर केवल घरेलू उत्पादन की कमी का असर नहीं है। वैश्विक बाजार की परिस्थितियां भी कीमतों को प्रभावित करती हैं। ब्राजील में गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल उत्पादन की ओर बढ़ने और मौसम संबंधी चुनौतियों के कारण वैश्विक चीनी आपूर्ति पर दबाव की बात सामने आई है। दूसरी ओर, त्योहारी मांग को देखते हुए जमाखोरी और कालाबाजारी की आशंका ने भी सरकार की चिंता बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश समेत कई स्थानों पर प्रशासन ने स्टॉक की निगरानी और गोदामों की जांच तेज की है। 30 दिन से अधिक का स्टॉक रखने वाले डीलरों पर भी निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।

विश्लेषण: क्या सिर्फ आयात से खत्म होगा चीनी संकट?

सरकार का तत्काल कदम बाजार में आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिहाज से प्रभावी हो सकता है। शुल्क-मुक्त आयात से घरेलू बाजार में अतिरिक्त चीनी उपलब्ध होगी और त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने पर आपूर्ति का दबाव कुछ कम किया जा सकता है। लेकिन लंबी अवधि का समाधान केवल आयात नहीं है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का घटता रकबा और चीनी उत्पादन में तेज गिरावट यह संकेत देती है कि खेती के स्तर पर भी स्थायी रणनीति की जरूरत है। किसानों को गन्ने की खेती के लिए बेहतर प्रोत्साहन, रोग नियंत्रण, उन्नत बीज, सिंचाई और समय पर भुगतान जैसी व्यवस्थाएं मजबूत करनी होंगी। साथ ही मक्का और धान की ओर किसानों के बढ़ते रुझान के पीछे मौजूद आर्थिक कारणों को समझना भी जरूरी है। यदि गन्ने की खेती किसानों के लिए लगातार कम आकर्षक होती गई तो भविष्य में चीनी उत्पादन को बनाए रखना और घरेलू मांग पूरी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

आगे क्या? आने वाले महीनों में तीन कारक सबसे महत्वपूर्ण होंगे—घरेलू चीनी उत्पादन, आयातित चीनी की उपलब्धता और त्योहारी सीजन की मांग। यदि आयात समय पर बाजार में पहुंचता है और जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण रहता है तो कीमतों में तेजी को सीमित किया जा सकता है। वहीं अगले गन्ना सीजन में किसानों का रुझान किस दिशा में जाता है, यह भी चीनी बाजार की भविष्य की तस्वीर तय करेगा।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में गन्ने का घटता रकबा और चीनी उत्पादन में 14 प्रतिशत की कमी घरेलू बाजार के लिए गंभीर संकेत है। इसके पीछे फसल परिवर्तन के साथ बीमारी, मौसम और वैश्विक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने 10 लाख टन शुल्क-मुक्त कच्ची चीनी के आयात का फैसला लेकर तत्काल आपूर्ति संकट से निपटने की कोशिश की है। लेकिन असली समाधान खेत से शुरू होगा। यदि किसानों को गन्ने की खेती आर्थिक रूप से आकर्षक बनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाते हैं, तभी चीनी बाजार में लंबे समय तक स्थिरता कायम रखी जा सकेगी।





चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच अब प्याज और अन्य सब्जियों के महंगे होने से आम आदमी की परेशानी बढ़ गई है। देश के कई शहरों में प्याज के दाम 60 से 70 रुपये किलो तक पहुंचने से घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। बारिश, सीमित सप्लाई और बढ़ती मांग को कीमतों में तेजी की प्रमुख वजह माना जा रहा है।

प्याज महंगा, सब्जियों के दाम भी बढ़े

प्याज के साथ टमाटर, मटर, गोभी और शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। बढ़ती महंगाई का असर बाजार में ग्राहकों की खरीदारी पर साफ दिखाई दे रहा है। पहले जहां परिवार दो-तीन किलो सब्जियां खरीदकर ले जाते थे, वहीं अब कई लोग आधा किलो या एक किलो में ही काम चलाने को मजबूर हैं। महंगी सब्जियों का असर केवल घरेलू रसोई तक सीमित नहीं है। दुकानदारों, होटल और ढाबा संचालकों के लिए भी बढ़ी हुई कीमतें चुनौती बन गई हैं। लागत बढ़ने के बावजूद ग्राहकों पर पूरा बोझ डालना आसान नहीं है, जिससे कारोबारियों के मुनाफे पर भी असर पड़ रहा है।

किसानों को मंडियों में बेहतर दाम से राहत

प्याज की बढ़ती कीमतों का एक दूसरा पहलू किसानों के लिए राहत भी लेकर आया है। नासिक समेत कई प्रमुख मंडियों में प्याज को बेहतर दाम मिलने से उत्पादकों को फायदा हो रहा है। हालांकि, उपभोक्ताओं के लिए यही तेजी चिंता का कारण बनी हुई है। बारिश के कारण सप्लाई प्रभावित होने और बाजार में उपलब्धता कम होने की स्थिति में कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में आने वाले समय में आवक और सप्लाई व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज उतारने की तैयारी तेज की

बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतारने की योजना शुरू की है। इसके अलावा अलग-अलग शहरों तक प्याज पहुंचाने के लिए 'कांदा एक्सप्रेस' का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य बाजार में उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों में तेजी को नियंत्रित करना है। अगर बाजार में सरकारी स्टॉक से पर्याप्त प्याज पहुंचता है तो खुदरा कीमतों पर कुछ राहत मिलने

की उम्मीद है। हालांकि, इसका असर किस स्तर तक और कितनी जल्दी दिखाई देता है, यह सप्लाई की मात्रा तथा स्थानीय बाजारों में मांग पर निर्भर करेगा। चीनी महंगी तो मंत्री के बयान पर सियासी बवाल

एक तरफ चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ाई है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। रक्षाबंधन से पहले इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान चीनी की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा—“अच्छा है चीनी और महंगी हो जाए।” विजयवर्गीय उस दौरान वृद्धजनों और दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे थे और बच्चों के साथ अंताक्षरी भी खेली। इसी दौरान चीनी के दाम को लेकर सवाल हुआ, जिस पर उनकी टिप्पणी सामने आई। त्योहारों के मौसम में चीनी की कीमतों में तेजी के बीच इस बयान को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे आम जनता की परेशानियों के प्रति असंवेदनशीलता से जोड़कर सवाल उठा सकते हैं, जबकि महंगाई का मुद्दा आने वाले दिनों में सियासी बहस का हिस्सा बन सकता है।

आम आदमी के सामने दोहरी चुनौती

चीनी और प्याज जैसी रोजमर्रा की जरूरत वाली वस्तुओं की कीमतों में एक साथ बढ़ोतरी घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव डालती है। खासकर त्योहारों के समय जब मिठाई और भोजन की खपत बढ़ती है, तब खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी का असर ज्यादा महसूस होता है। फिलहाल सरकार के सामने चुनौती बाजार में पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने और जमाखोरी जैसी गतिविधियों पर नजर रखने की है। वहीं उपभोक्ताओं की नजर इस बात पर है कि सरकारी हस्तक्षेप के बाद प्याज और चीनी की कीमतों में कब तक राहत मिलती है।





दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए प्रदर्शन ने एक बार फिर आरक्षण और शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों, युवाओं और सर्वर्ण समाज के लोगों ने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और यूजीसी के कुछ नए नियमों पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकारी सुविधाओं और अवसरों का आधार आर्थिक स्थिति होना चाहिए। वहीं कई लोगों ने आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग भी उठाई। देखते ही देखते यह मुद्दा सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति के केंद्र में आ गया। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक हर जगह इसी विषय पर चर्चा शुरू हो गई। क्योंकि मामला शिक्षा, रोजगार और सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा है, इसलिए इसका असर सीधे करोड़ों युवाओं और परिवारों तक पहुंच रहा है।

यूजीसी और आरक्षण को लेकर क्यों बढ़ा विवाद



इस पूरे विवाद की दूसरी बड़ी वजह यूजीसी से जुड़े कुछ नए प्रस्ताव और नियम हैं, जिन पर छाल संगठनों और कई सामाजिक समूहों ने सवाल उठाए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नई व्यवस्थाएं शिक्षा के अवसरों में असमानता बढ़ा सकती हैं। हालांकि सरकार और यूजीसी की ओर से लगातार यह कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। लेकिन विरोध कर रहे संगठनों का मानना है कि किसी भी बदलाव से पहले व्यापक चर्चा और सभी वर्गों की राय ली जानी चाहिए। यही कारण है कि यूजीसी के मुद्दे के साथ आरक्षण की बहस भी जुड़ गई। आंदोलन में शामिल कई लोगों का कहना था कि शिक्षा और नौकरियों में अवसरों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। दूसरी ओर आरक्षण समर्थक संगठन इसे सामाजिक न्याय से जुड़ा विषय बताते हुए किसी भी बदलाव का विरोध कर रहे हैं।

राजनीतिक दलों ने संभाला मोर्चा

जैसे-जैसे आंदोलन की चर्चा बढ़ी, राजनीतिक दल भी खुलकर मैदान में उतर आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण में किसी भी तरह की छेड़छाड़ का विरोध किया और इसे पिछड़े तथा वंचित वर्गों के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने भी स्पष्ट कहा कि आरक्षण संविधान से मिला अधिकार है और इसकी समीक्षा भी स्वीकार नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी आरक्षण के समर्थन में सख्त बयान दिए। इससे साफ हो गया कि यह बहस सिर्फ शिक्षा या रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए भी बेहद संवेदनशील मुद्दा बन चुकी है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जहां जातीय और सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं, वहां इस मुद्दे को लेकर नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है।

आंदोलन के भीतर मतभेद और नई बहस

इस आंदोलन के दौरान एक नया मोड़ तब आया जब आंदोलन से जुड़े प्रमुख चेहरों में शामिल हर्ष दुबे की उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई। इसके बाद आंदोलन के भीतर ही अलग-अलग राय सामने आने लगीं। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि जब मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हैं तो राज्य स्तर पर बातचीत क्यों की गई। वहीं दूसरी ओर हर्ष दुबे ने कहा कि सरकार को मांगों पर विचार करने का समय दिया गया है और जरूरत पड़ने पर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इस घटनाक्रम ने आंदोलन के भीतर रणनीति और नेतृत्व को लेकर नई बहस छेड़ दी। हालांकि इससे यह भी साफ हुआ कि यह आंदोलन सिर्फ एक दिन का विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय तक चलने वाली राजनीतिक और सामाजिक चर्चा की संभावना है।

2027 और 2029 के चुनावों पर क्या होगा असर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में आरक्षण, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक तरफ सर्वर्ण समाज का एक हिस्सा बदलाव की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दलित, पिछड़े और आरक्षित वर्गों से जुड़े संगठन और नेता आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए मजबूती से उसके पक्ष में खड़े हैं। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल के लिए संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य बड़े राज्यों में जहां सामाजिक समीकरण चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा हैं, वहां इस बहस का असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सरकार की ओर से आरक्षण व्यवस्था में किसी बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन जंतर-मंतर से उठी आवाज ने इतना जरूर साबित कर दिया है कि शिक्षा, आरक्षण और अवसरों की समानता पर शुरू हुई यह बहस आने वाले समय में चुनावी मंचों तक पहुंचेगी। यही वजह है कि अब देश की नजर इस बात पर है कि सरकार, राजनीतिक दल और आंदोलनकारी आगे कौन सा रास्ता चुनते हैं।



नोएडा एयरपोर्ट के पास घर का सपना होगा आसान!

YEIDA की 2 नई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम पर नजर



कम आय वर्ग के लिए
40 वर्गमीटर के प्लॉट

आम लोगों के लिए
162 से 300 वर्गमीटर के प्लॉट



साजिद अली
विशेष सलाहदाता



नोएडा एयरपोर्ट के बेहद करीब



बेहतरीन कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर



सुरक्षित निवेश, उज्जवल भविष्य



पारदर्शी योजना, आसान प्रक्रिया

ग्रेटर नोएडा/जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में रिहायशी जमीन की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) दो नई रेजिडेंशियल प्लॉट योजनाएं लाने की तैयारी कर रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दोनों योजनाओं की घोषणा अक्टूबर में नवरात्रि के दौरान किए जाने की संभावना है। इन प्रस्तावित योजनाओं की खासियत यह है कि इनमें अलग-अलग आय वर्ग और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्लॉट के आकार तय किए जा रहे हैं। पहली योजना कम आय वर्ग के लोगों के लिए प्रस्तावित है, जबकि दूसरी योजना आम जनता के लिए होगी।

कम आय वर्ग के लिए 40 वर्गमीटर का प्लॉट



प्रस्तावित पहली योजना को कम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 40 वर्गमीटर के प्लॉट दिए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य सीमित बजट वाले लोगों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास विकसित हो रहे क्षेत्र में अपना घर बनाने का अवसर उपलब्ध कराना है। दूसरी

और आम जनता के लिए प्रस्तावित योजना में 162 से 300 वर्गमीटर तक के प्लॉट शामिल किए जाने की जानकारी है। दोनों योजनाएं सेक्टर-5ए में प्रस्तावित हैं, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास विकसित हो रहे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है। YEIDA के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शैलेंद्र भाटिया के अनुसार प्राधिकरण फिलहाल योजनाओं की बारीकियों पर काम कर रहा है। प्लॉटों की अंतिम संख्या और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद सामने आएगी।

पहले प्लॉट मिल चुका है तो नई योजना में आवेदन नहीं



नई योजनाओं में अधिक से अधिक नए आवेदकों को अवसर देने के लिए पात्रता से जुड़ी महत्वपूर्ण शर्त प्रस्तावित है। जिन लोगों को पहले नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण या YEIDA की किसी रेजिडेंशियल प्लॉट योजना में प्लॉट आवंटित हो चुका है, वे इन नई योजनाओं में आवेदन नहीं कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे आवेदकों को दोबारा लाभ लेने से रोकना है, जिन्हें पहले ही किसी प्राधिकरण की आवासीय प्लॉट योजना का लाभ मिल

चुका है।

36,260 रुपये प्रति वर्गमीटर है मौजूदा आवंटन दर

उपलब्ध जानकारी के अनुसार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में रेजिडेंशियल प्लॉट की मौजूदा आवंटन दर 36,260 रुपये प्रति वर्गमीटर बताई गई है। हालांकि, प्रस्तावित दोनों नई योजनाओं के लिए अंतिम कीमत, कुल प्लॉट संख्या, पंजीकरण शुल्क और अन्य शर्तें प्राधिकरण की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होंगी। इसलिए संभावित आवेदकों के लिए जरूरी होगा कि वे आवेदन से पहले YEIDA की आधिकारिक अधिसूचना में पालता, दर, भुगतान व्यवस्था और अन्य नियमों को ध्यान से देखें।



973 प्लॉट के लिए आए थे 1.1 लाख से ज्यादा आवेदन

नई योजनाओं को लेकर लोगों की दिलचस्पी का अंदाजा YEIDA की पिछली आवासीय प्लॉट योजना से लगाया जा सकता है। अप्रैल में घोषित योजना में 973 प्लॉट शामिल थे और इसके लिए 1.1 लाख से अधिक वैध आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदन की संख्या और उपलब्ध प्लॉटों के बीच बड़ा अंतर बताता है कि नोएडा एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में रिहायशी जमीन को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी मजबूत है। ऐसे में नई योजनाओं में भी बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना है।



नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की आर्थिक और रियल एस्टेट संभावनाएं भी तेजी से बदल रही हैं। बेहतर हवाई संपर्क के साथ औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की उम्मीद ने इस पूरे क्षेत्र को निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण बना दिया है। एयरपोर्ट के आसपास रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ आवास की मांग बढ़ने की संभावना भी है। यही वजह है कि रिहायशी प्लॉट योजनाओं को केवल जमीन की बिक्री के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि यह क्षेत्र के भविष्य के शहरी विस्तार से

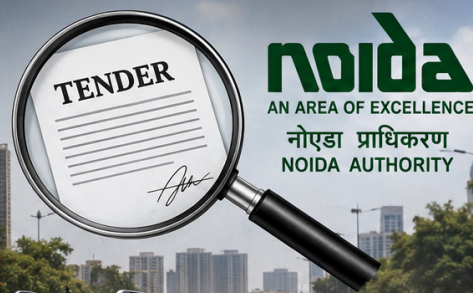
भी जुड़ा विषय बन गया है।

विश्लेषण: मांग के पीछे सिर्फ एयरपोर्ट नहीं

यमुना क्षेत्र में रिहायशी प्लॉट की बढ़ती मांग को केवल नोएडा एयरपोर्ट से जोड़कर देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी। एयरपोर्ट के साथ-साथ औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और प्रस्तावित विकास परियोजनाएं मिलकर इस क्षेत्र की मांग को प्रभावित कर रही हैं। कम आय वर्ग के लिए अलग योजना लाने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्राधिकरण क्षेत्र के विकास के साथ अलग-अलग आय वर्ग के लोगों के लिए आवासीय विकल्प तैयार करने पर ध्यान दे रहा है। हालांकि, मांग बहुत अधिक होने की स्थिति में प्लॉट मिलना आसान नहीं होगा। पिछली योजना में 973 प्लॉट के मुकाबले 1.1 लाख से अधिक आवेदन इसका स्पष्ट संकेत हैं। इसलिए नई योजनाओं में आवेदन करने वाले लोगों को इसे निवेश के साथ-साथ लंबी अवधि की आवासीय योजना के नजरिए से देखना चाहिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास YEIDA की प्रस्तावित दो नई रेजिडेंशियल प्लॉट योजनाएं यमुना क्षेत्र के तेजी से बदलते रियल एस्टेट परिदृश्य का संकेत देती हैं। 40 वर्गमीटर के छोटे प्लॉट से लेकर 300 वर्गमीटर तक के विकल्प अलग-अलग जरूरत वाले लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। अक्टूबर में नवरात्रि के दौरान प्रस्तावित घोषणा के बाद प्लॉटों की संख्या, अंतिम कीमत और आवेदन की शर्तों की तस्वीर साफ होगी। पिछली योजना में मिले जबरदस्त रिसॉन्स को देखते हुए इन योजनाओं पर भी आवेदकों और निवेशकों की नजरें टिकी रहेंगी।



नोएडा की सड़कों की बदहाली पर सवाल, 2022 से सभी टेंडरों की होगी जांच



500 करोड़ रुपये के सड़क कार्यों के बावजूद धूल और उखड़ी गिटी से परेशान वाहन चालक



प्राधिकरण ने लापरवाही पर कार्रवाई के दिए संकेत



नोएडा। शहर में करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद कई प्रमुख सड़कों की खराब हालत ने नोएडा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क निर्माण और रिसर्फेसिंग से जुड़े कार्यों में कथित लापरवाही को देखते हुए प्राधिकरण ने वर्ष 2022 से अब तक जारी सभी संबंधित टेंडरों की जांच के आदेश दिए हैं। जांच का उद्देश्य सड़क निर्माण की गुणवत्ता, काम पूरा होने की समयसीमा और ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करना है। लापरवाही सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के सर्किल-1 से सर्किल-5 तक करीब 150 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और रिसर्फेसिंग के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए गए थे। अलग-अलग सड़कों का काम कई ठेकेदारों और एजेंसियों को सौंपा गया। इसके बावजूद शहर की कई प्रमुख सड़कों पर निर्माण के कुछ समय बाद ही गड्ढे, उखड़ी गिट्टी और धूल जैसी समस्याएं सामने आने लगी हैं।

500 करोड़ के काम पर उठे सवाल

नोएडा में सड़क निर्माण और रिसर्फेसिंग का काम बड़े स्तर पर कराया गया था। कई परियोजनाओं में काम समय पर पूरा नहीं होने पर ठेकेदारों की ओर से पश्चिमी एशिया में संकट के कारण तारकोल और बिटुमिन की आपूर्ति प्रभावित होने तथा कच्चे माल की कमी को वजह बताया गया। हालांकि, निर्माण कार्यों में देरी और खराब गुणवत्ता को लेकर अब प्राधिकरण की निगरानी व्यवस्था भी सवाल के घेरे में है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद यदि सड़क कुछ ही समय में खराब हो जाती है तो निर्माण की गुणवत्ता और ठेकेदारों द्वारा अपनाए गए मानकों की जांच जरूरी हो जाती है। इसी को देखते हुए वर्ष 2022 से अब तक के सड़क निर्माण और रिसर्फेसिंग से जुड़े टेंडरों की समीक्षा का निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सेक्टर-18 से सेक्टर-37 तक सड़क की हालत खराब

शहर की कई प्रमुख सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सेक्टर-18 से सेक्टर-37 और सेक्टर-51 तक जाने वाले मार्ग,

सेक्टर-49 से 12/22 चौकी तक की सड़क और सेक्टर-31 के सामने वाली सड़क पर धूल और बिखरी गिट्टी की समस्या बताई जा रही है। सेक्टर-18 से सेक्टर-37 के बीच मुख्य मार्ग पर सड़क की खराब स्थिति का सबसे ज्यादा असर बाइक और ई-रिक्शा चालकों पर पड़ रहा है। सड़क पर जगह-जगह उखड़ी गिट्टी और उड़ती धूल के कारण वाहन चालकों को धीमी गति से और अतिरिक्त सावधानी के साथ चलना पड़ रहा है। स्टेडियम चौक से सेक्टर-49 तक का मार्ग भी खराब स्थिति वाले प्रमुख मार्गों में शामिल बताया गया है।

सड़क की गुणवत्ता बनी जांच का केंद्र

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन सड़कों पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, उनकी गुणवत्ता की निगरानी किस स्तर पर हुई। यदि किसी सड़क की सतह निर्माण या रिसर्फेसिंग के कुछ समय बाद ही उखड़ने लगे तो निर्माण सामग्री, कार्यप्रणाली और गुणवत्ता परीक्षण की जांच जरूरी हो जाती है। सड़क पर बिखरी गिट्टी और धूल केवल यातायात की समस्या नहीं है। इससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का जोखिम भी बढ़ सकता है। खासकर व्यस्त मार्गों पर अचानक ब्रेक लगाने या गिट्टी पर वाहन फिसलने की स्थिति गंभीर हो सकती है।

विश्लेषण: सिर्फ टेंडर नहीं, पूरी प्रक्रिया की जांच जरूरी वर्ष 2022 से सभी टेंडरों की जांच का निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क निर्माण की गुणवत्ता केवल ठेकेदार पर निर्भर नहीं होती। टेंडर की शर्तें, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, साइट निरीक्षण, भुगतान से पहले सत्यापन, काम पूरा होने की रिपोर्ट और बाद की गुणवत्ता जांच—पूरी प्रक्रिया की भूमिका होती है। यदि जांच में यह सामने आता है कि ठेकेदारों ने निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया तो कार्रवाई के साथ उनसे जवाबदेही तय करना जरूरी होगा। वहीं यदि निगरानी या निरीक्षण में विभागीय स्तर पर कमी सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा होनी चाहिए। शहर के नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे। खराब सड़कों की मरम्मत, गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई जमीन पर दिखाई देनी चाहिए।



भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ



**नेपाल में
जलप्रलय का
भयावह मंजर:
600 से ज्यादा
की मौत,
2482 लापता,
320 भारतीयों की
तलाश जारी**

का उमांडू। नेपाल में भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। रसुवा क्षेत्र में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने घरों, सड़कों, पुलों और वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, हादसे में खबर लिखे जाने तक अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत, 2482 लापता और 320 भारतीयों की तलाश जारी है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने से राहत और बचाव अभियान के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। भोटेकोशी नदी में आया सैलाब बेहद तेज था। मलबे और पानी के तेज बहाव ने नदी के आसपास के इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। कई स्थानों पर संपर्क मार्ग बाधित हो गए और पुलों के बह जाने से प्रभावित क्षेत्रों तक राहत पहुंचाना मुश्किल हुआ है। नेपाल सेना और स्थानीय रेस्क्यू टीमों लगातार अभियान चला रही हैं।

35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बहे

बाढ़ की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं। इसके अलावा 13 जलविद्युत परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। पुलों और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से कई इलाकों का संपर्क प्रभावित हुआ है। बाढ़ के पानी के साथ आए मलबे ने कई घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने के कारण प्रशासन के सामने उनकी तलाश और सुरक्षित निकासी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

नेपाल सेना ने संभाला मोर्चा, हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू

तबाही के बाद नेपाल सेना और अन्य बचाव दलों ने बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया है। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचने में भौगोलिक परिस्थितियां भी चुनौती बनी हुई हैं। रेस्क्यू अभियान के दौरान लापता लोगों की तलाश के साथ-साथ प्रभावित परिवारों तक भोजन, चिकित्सा सहायता और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के कारण राहत सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया कई जगह कठिन हो गई है।

भारत ने नेपाल के लिए बढ़ाया मदद का हाथ

नेपाल में आई इस प्राकृतिक आपदा के बाद भारत ने भी सहायता की पेशकश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत की ओर से HADR और मेडिकल सहायता भी राहत कार्यों के लिए पहुंचाई गई है। भारत और नेपाल के बीच भौगोलिक और सामाजिक संबंधों को देखते हुए इस आपदा का असर सीमा के आसपास के क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। नेपाल की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की स्थिति में भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी सतर्कता जरूरी हो जाती है।

बिहार में भी बढ़ी चिंता

भोटेकोशी और नेपाल के अन्य हिस्सों में भारी बारिश तथा बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बिहार के नदी किनारे बसे इलाकों में भी चिंता बढ़ी है। नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर में वृद्धि का असर बिहार के निचले इलाकों पर पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को निगरानी बढ़ानी पड़ रही है। हालांकि बाढ़ का तत्काल सबसे बड़ा असर नेपाल के रसुवा क्षेत्र में दिखाई दिया है, लेकिन हिमालयी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं केवल स्थानीय आपदा तक सीमित नहीं रहतीं। नदियों का जलप्रवाह, पुलों और सड़कों का टूटना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था प्रभावित होना व्यापक मानवीय और आर्थिक संकट पैदा कर सकता है।

आपदा ने नेपाल की संवेदनशीलता फिर उजागर की

भोटेकोशी की बाढ़ ने नेपाल के पर्वतीय और नदी किनारे बसे क्षेत्रों की आपदा संवेदनशीलता को एक बार फिर सामने ला दिया है। भारी बारिश के दौरान अचानक आने वाली बाढ़ बेहद कम समय में बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में समय पर चेतावनी, मजबूत पुल-पुलिया, सुरक्षित आवास और प्रभावी आपदा प्रबंधन व्यवस्था की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल नेपाल में प्राथमिकता लापता लोगों की तलाश, प्रभावित लोगों की सुरक्षित निकासी और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने की है। भारत की ओर से सहायता मिलने से राहत अभियान को अतिरिक्त सहयोग मिलने की उम्मीद है।



नोएडा में कचरे से बनेगी गैस और जैविक खाद

नोएडा। शहर में रोजाना निकलने वाले कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में नोएडा प्राधिकरण बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सेक्टर-145 में करीब 12 एकड़ जमीन पर 600 मीट्रिक टन क्षमता का कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट में शहर से निकलने वाले जैविक कचरे का इस्तेमाल कर कंप्रेस्ड बायोगैस के साथ जैविक खाद तैयार की जाएगी। परियोजना को लेकर प्राधिकरण की ओर से मसौदा तैयार किया जा रहा है। शर्तों को पूरा करने वाली पीएसयू कंपनी के साथ जल्द ही एमओयू किए जाने की तैयारी है। खास बात यह है कि प्लांट लगाने और उसके संचालन पर नोएडा प्राधिकरण को अपनी ओर से कोई राशि खर्च नहीं करनी होगी।

12 एकड़ में बनेगा CBG प्लांट, कंपनी करेगी संचालन

नोएडा प्राधिकरण सेक्टर-145 में प्लांट स्थापित करने के लिए कंपनी को करीब 12 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगा। प्लांट लगाने, मशीनरी स्थापित करने और इसके संचालन की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी। प्राधिकरण के स्तर पर फिलहाल परियोजना की शर्तों और नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली पीएसयू कंपनी के साथ एमओयू किया जाएगा। इसके बाद प्लांट निर्माण और संचालन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। शहर में कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें कचरे को केवल हटाने के बजाय उससे उपयोगी ऊर्जा और जैविक उत्पाद तैयार करने की योजना है।

रोज बनेगी 16 हजार किलो CBG और 100 टन खाद

प्रस्तावित प्लांट में रोजाना करीब 16 हजार किलो कंप्रेस्ड बायोगैस तैयार होने का अनुमान है। इसके साथ लगभग 100 टन जैविक खाद भी तैयार की जाएगी। कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG को प्राकृतिक गैस के वैकल्पिक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग गैस आधारित वाहनों के अलावा अन्य उपयुक्त ऊर्जा जरूरतों में भी किया जा सकेगा। कचरे से जैविक खाद तैयार होने से कृषि और हरित क्षेत्र में इसके इस्तेमाल की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यानी एक तरफ शहर के कचरे का निस्तारण होगा और दूसरी तरफ उससे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

प्राधिकरण नहीं करेगा एक रुपये का खर्च

इस परियोजना की सबसे अहम बात यह है कि प्लांट लगाने और उसके संचालन के लिए नोएडा प्राधिकरण को एक भी रुपये खर्च नहीं करना होगा। प्राधिकरण की भूमिका मुख्य रूप से जमीन उपलब्ध कराने और कचरे को प्लांट तक पहुंचाने की होगी। कचरे को प्राइमरी कलेक्शन सेंटर से सेक्टर-145 स्थित प्लांट तक पहुंचाने की व्यवस्था प्राधिकरण करेगा। इसके लिए डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्तमान में नोएडा में करीब 250 वाहन डोर-टू-डोर

कचरा संग्रहण के लिए संचालित किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था के जरिए कचरे को अलग-अलग स्तर पर एकत्र कर प्रस्तावित प्लांट तक पहुंचाने की योजना है।

कचरे से बनेगा ग्रीन कोल, कार्बन क्रेडिट का भी लाभ

CBG प्लांट और ठोस कचरा निस्तारण प्रक्रिया से टेरिफाइड चारकोल और ग्रीन कोल जैसे उत्पाद तैयार किए जाने की योजना है। इनका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर किया जा सकता है। इसके अलावा कचरे से ऊर्जा और जैविक उत्पाद तैयार करने वाली परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलने की उम्मीद है। परियोजना से 30 प्रतिशत तक कार्बन क्रेडिट मिलने की संभावना भी बताई जा रही है। कार्बन क्रेडिट के जरिए पर्यावरणीय लाभ को आर्थिक मूल्य में बदलने का अवसर मिलता है।

कचरे के ढेर, बदबू और आग की समस्या होगी कम

नोएडा में रोजाना बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है। इसके वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था मजबूत होने से खुले में कूड़ा जमा होने, उससे बदबू आने और कूड़े के ढेर में आग लगने जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। प्लांट के जरिए जैविक कचरे का इस्तेमाल ऊर्जा और खाद बनाने में होने से लैंडफिल पर दबाव भी घटेगा। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भी यह परियोजना उपयोगी साबित हो सकती है।

नोएडा में रोज निकलता है इतना कचरा

कचरे का प्रकार	रोजाना मात्रा
गीला कचरा	900 मीट्रिक टन
सूखा कचरा	600 मीट्रिक टन
सीएंडडी वेस्ट	400 मीट्रिक टन
कुल	1,900 मीट्रिक टन
600 मीट्रिक टन	प्रस्तावित CBG प्लांट की क्षमता
12 एकड़	प्लांट के लिए जमीन
16,000 किलो	रोजाना अनुमानित CBG उत्पादन
100 टन	रोजाना जैविक खाद उत्पादन
250 वाहन	डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था में
30% तक	संभावित कार्बन क्रेडिट

नोएडा के सेक्टर-145 में 12 एकड़ जमीन पर 600 मीट्रिक टन क्षमता का CBG प्लांट प्रस्तावित है। इसमें रोजाना करीब 16 हजार किलो बायोगैस और 100 टन जैविक खाद तैयार होगी। प्राधिकरण जमीन और कचरा उपलब्ध कराएगा, जबकि कंपनी प्लांट लगाएगी और संचालन करेगी।

यूपी में गंगा-यमुना समेत कई नदियां उफान पर, 13 जिलों के 173 गांव प्रभावित

बारिश और बाढ़ के दोहरे संकट से
जूझता उत्तर प्रदेश,
राहत और बचाव व्यवस्था
की हुई व्यापक तैयारी



लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू और गोमती समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ और जलभराव की स्थिति गंभीर हुई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 13 जिलों के 173 गांव प्रभावित हैं और 84 हजार से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। नदी किनारे बसे इलाकों के साथ-साथ कई स्थानों पर खेतों में पानी भरने से किसानों की चिंता भी बढ़ी है। बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने प्रदेश के कई हिस्सों में प्रशासन के सामने राहत एवं बचाव की चुनौती बढ़ा दी है। प्रयागराज से वाराणसी और कानपुर से बहराइच तक संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा कर प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दे रहे हैं।

प्रयागराज में गंगा-यमुना के उफान से बढ़ी मुश्किलें

प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर संगम क्षेत्र के अलावा निचले और रिहायशी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। कई स्थानों पर पानी घरों तक पहुंचने से परिवारों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लगातार बारिश ने शहर में जलभराव की समस्या को भी बढ़ाया है। कई घरों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और आवश्यक राहत उपलब्ध कराने की है।



वाराणसी के घाट जलमग्न, कानपुर के गांवों पर निगरानी

वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाटों की सीढ़ियां पानी में समा गई हैं। नमो घाट समेत कई घाटों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मणिकर्णिका

और हरिश्चंद्र घाट तक पानी पहुंचने से आसपास के लोगों और कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। गंगा आरती के आयोजन में भी परिस्थितियों के अनुसार इंतजाम करने पड़ रहे हैं। कानपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 176 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। निचले इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन की ओर से 35 स्थानों पर पुलिस पोस्ट स्थापित की गई हैं। NDRF की टीम, फ्लड कंपनी और करीब 100 प्रशिक्षित गोताखोरों को भी तैयार रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके।

1589 बाढ़ चौकियां और 1263 राहत शिविर तैयार

बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश में व्यापक राहत तंत्र सक्रिय किया गया है। 1589 बाढ़ चौकियां और 1263 रिलीफ शेल्टर तैयार किए गए हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ भोजन और फूड पैकेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। राहत कार्यों के लिए नावों और मोटरबोट के साथ गोताखोरों और बचाव कर्मियों की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात हैं। वहीं, पानी में डूबी फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए राजस्व और कृषि विभाग को भी सक्रिय किया गया है।

मौसम और जलस्तर की चुनौती ने बढ़ाई प्रशासन की जिम्मेदारी

दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश की संभावना ने प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ाई है। लगातार बारिश की स्थिति में नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है, जिससे मौजूदा प्रभावित क्षेत्रों पर दबाव बढ़ने की आशंका बनी रहती है। वहीं, मौसम में सुधार होने पर नदियों के जलस्तर में कमी आने और प्रभावित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन के लिए नदी के जलस्तर, बारिश और संवेदनशील इलाकों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

विश्लेषण: बाढ़ से निपटने में राहत के साथ दीर्घकालिक तैयारी जरूरी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या केवल नदी के बढ़ते जलस्तर तक सीमित नहीं है। लगातार बारिश होने पर ग्रामीण इलाकों के साथ शहरों में जलभराव की समस्या भी गंभीर हो जाती है। ऐसे में राहत शिविरों और बाढ़ चौकियों की व्यवस्था तत्काल सहायता के लिए महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए भी बाढ़ का असर गंभीर हो सकता है। खेतों में लंबे समय तक पानी जमा रहने से फसलों को नुकसान पहुंचता है और कृषि गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इसलिए फसल नुकसान का समयबद्ध आकलन और प्रभावित किसानों तक सहायता पहुंचाना राहत व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1589 बाढ़ चौकियां और 1263 राहत शिविर तैयार किया जाना प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारी को दर्शाता है। हालांकि इन व्यवस्थाओं की वास्तविक प्रभावशीलता इस बात से तय होगी कि प्रभावित क्षेत्रों में जरूरत के समय राहत कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से पहुंचती है।



कौन हैं CEC ज्ञानेश कुमार? ट्रंप ने की भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ



जानिए मुख्य चुनाव आयुक्त का सफर

नई दिल्ली। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक टिप्पणी के बाद अंतरराष्ट्रीय चर्चा में आया है। ट्रंप ने अमेरिका में मतदाता पहचान से जुड़े कड़े नियमों की वकालत करते हुए भारत की चुनावी व्यवस्था का उदाहरण दिया और ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय मतदाता पहचान व्यवस्था को अमेरिका के लिए एक उदाहरण के तौर पर पेश किया। ट्रंप के बयान के बाद यह सवाल स्वाभाविक रूप से चर्चा में आया कि आखिर भारत के मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कौन हैं और प्रशासनिक सेवा से निर्वाचन आयोग तक उनका सफर कैसा रहा है।

1988 बैच के IAS अधिकारी से बने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त

ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले वह निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार उन्हें 15 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति 2023 में बनाए गए नए कानून के तहत हुई। इस व्यवस्था के तहत नियुक्त होने वाले वह पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रशासनिक करियर के दौरान ज्ञानेश कुमार ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। केरल में उन्होंने सब-कलेक्टर, जिला कलेक्टर और कोच्चि नगर आयुक्त जैसे पदों पर काम किया। केंद्र सरकार में भी उन्होंने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।

IIT कानपुर से हार्वर्ड तक की पढ़ाई

ज्ञानेश कुमार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी उल्लेखनीय रही है। उन्होंने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में B.Tech किया। इसके बाद ICFAI से बिजनेस फाइनेंस की पढ़ाई की। उन्होंने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का अध्ययन भी किया। तकनीकी शिक्षा और प्रशासनिक अनुभव का यह संयोजन उनके करियर की खास विशेषताओं में शामिल रहा है। केंद्र सरकार में जिम्मेदारियां संभालने के दौरान उन्होंने नीति निर्माण और प्रशासन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में काम किया।

सहकारिता सचिव से निर्वाचन आयोग तक

मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले ज्ञानेश कुमार केंद्र सरकार में सहकारिता सचिव के पद पर कार्यरत थे। वह 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त हुए और इसके बाद 15 मार्च 2024 को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए। करीब एक साल के भीतर उन्हें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी मिली। CEC के रूप में उनके कार्यकाल में लोकसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों से संबंधित निर्वाचन प्रक्रिया शामिल रही है। 2026 में भारत ने International IDEA के Council of Member States की अध्यक्षता भी संभाली, जिसमें ज्ञानेश कुमार भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

विश्लेषण: ट्रंप के बयान के बाद क्यों महत्वपूर्ण हुआ नाम?

ज्ञानेश कुमार का नाम अमेरिकी राजनीतिक बहस में इसलिए आया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान व्यवस्था को अमेरिका में फोटो आईडी की अनिवार्यता के अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण के तौर पर पेश किया। यह घटनाक्रम भारत की चुनावी व्यवस्था की अंतरराष्ट्रीय चर्चा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारत में चुनाव संचालन, मतदाता सूची, पहचान और मतदान प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग की भूमिका केंद्रीय है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम किसी विदेशी राजनीतिक बहस में संदर्भ के रूप में इस्तेमाल होना आयोग की भूमिका को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में लाता है। हालांकि, ट्रंप के बयान को भारत की चुनावी व्यवस्था पर व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र के रूप में देखना उचित नहीं होगा।

प्रशासनिक अनुभव बना बड़ी जिम्मेदारी का आधार

ज्ञानेश कुमार का करियर राज्य प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार और फिर निर्वाचन आयोग तक फैला हुआ है। केरल में फील्ड प्रशासन से लेकर केंद्र में मंत्रालयों की जिम्मेदारियों और सहकारिता सचिव के पद तक का अनुभव उनके प्रशासनिक सफर को व्यापक बनाता है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन प्रक्रिया में विश्वसनीयता, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है।

IND vs SL:

चोट के बाद ऋषभ पंत की शानदार वापसी, जड़ा दमदार अर्धशतक; धोनी का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा



कोलंबो। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शानदार वापसी करते हुए 63 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। पहले दिन कलाई पर चोट लगने के बाद रिटायर्ड हर्ट हुए पंत की बल्लेबाजी को लेकर चिंता थी, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन मैदान पर उतरकर न सिर्फ अर्धशतक पूरा किया, बल्कि भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। पंत ने ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारत को मजबूत स्कोर की ओर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने अंततः 503/9 पर पारी घोषित की और दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका को 8/2 पर रोक दिया।

पंत ने तोड़ा एमएस धोनी का रिकॉर्ड



63 रन की पारी के दौरान पंत ने पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी का विदेशी या तटस्थ टेस्ट मैचों में भारतीय विकेटकीपर द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंत के नाम अब विदेशी/न्यूट्रल टेस्ट में विकेटकीपर के तौर पर 3,662 रन हो गए हैं, जबकि धोनी ने इस तरह के मैचों में 2,496 रन बनाए थे। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि पंत ने अपेक्षाकृत कम टेस्ट मैचों में यह मुकाम हासिल किया है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाने की क्षमता उन्हें भारतीय टेस्ट टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में शामिल करती है।

चोट के बाद मैदान पर लौटे और बना दिया इतिहास

पहले दिन श्रीलंकाई गेंदबाज लाहिरू कुमारा की गेंद कलाई पर लगने के बाद पंत को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था। इसके बाद उनके दूसरे दिन बल्लेबाजी करने को लेकर सवाल उठ रहे थे। टीम प्रबंधन ने बाद में संकेत दिया कि चोट गंभीर नहीं है। दूसरे दिन पंत ने मैदान पर वापसी की और अपनी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया। इस पारी ने न सिर्फ भारत की स्थिति मजबूत की बल्कि उनके नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हुए। इसी मैच में पंत ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने 2,948 रन के साथ शुभमन गिल के 2,917 रन के आंकड़े को पीछे छोड़ा।

एक ही दिन में कई बड़े रिकॉर्ड

कोलंबो टेस्ट पंत के लिए रिकॉर्ड से भरा रहा। धोनी का विदेशी टेस्ट रन रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी आगे बढ़े। पंत ने एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में 102 छक्कों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भी पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया था।

पंत की वापसी ने बढ़ाया टीम इंडिया का भरोसा

चोट के बाद पंत की 63 रनों की पारी भारतीय टीम के लिए मनोबल बढ़ाने वाली रही। खास बात यह रही कि उन्होंने मुश्किल परिस्थिति के बावजूद अपनी स्वाभाविक आक्रामक बल्लेबाजी को जारी रखा। कोलंबो में भारत की पारी 503/9 पर घोषित होने के बाद गेंदबाजों ने भी शानदार शुरुआत की और श्रीलंका को दिन का खेल खत्म होने तक 8/2 पर रोक दिया। ऐसे में भारत ने दूसरे टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पंत के लिए यह अर्धशतक सिर्फ एक पारी नहीं, बल्कि चोट के बाद शानदार वापसी और रिकॉर्ड बुक में एक और बड़ा अध्याय साबित हुआ।



मुं बई। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत और अभिनेत्री तापसी पन्नू के बीच पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में है। तापसी पन्नू की हालिया टिप्पणी के बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कंगना ने तापसी पर निशाना साधते हुए उनकी परवरिश और माता-पिता को लेकर भी टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों अभिनेत्रियों के बीच पुरानी बयानबाजी फिर सुर्खियों में आ गई है। तापसी इन दिनों अपनी फिल्म 'गांधारी' के प्रचार में व्यस्त हैं। इसी दौरान एक कार्यक्रम में उनसे कंगना के साथ विवाद और सुलह को लेकर सवाल पूछा गया। तापसी ने कहा कि वह कंगना से न तो उस समय मिली थीं, जब विवाद शुरू हुआ था और न ही अब मिली हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कंगना के बारे में उनकी राय उनकी अपनी परवरिश, बातचीत के तरीके और चीजों को देखने के नजरिए को दर्शाती है।

तापसी के बयान पर भड़की कंगना

तापसी की टिप्पणी सामने आने के बाद कंगना ने सोशल मीडिया के जरिए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तापसी को लेकर 'सस्ती कॉपी' जैसी टिप्पणी की और आरोप लगाया कि तापसी ने उनके माता-पिता और परवरिश का मजाक उड़ाया है। कंगना ने यह भी कहा कि वह सामान्य तौर पर किसी विवाद में माता-पिता को शामिल नहीं करतीं, लेकिन इस बार उन्होंने तापसी के माता-पिता को लेकर भी टिप्पणी की। उनकी प्रतिक्रिया में तापसी की तुलना उनके साथ करते हुए कई व्यक्तिगत टिप्पणियों की गईं। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों अभिनेत्रियों के समर्थकों के बीच भी बहस तेज हो गई है।

करीब आठ साल पुराना विवाद फिर चर्चा में

कंगना और तापसी के बीच विवाद नया नहीं है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 के आसपास हुई थी। उस समय तापसी से एक इंटरव्यू में कंगना को लेकर सवाल किया गया था। तापसी के जवाब के बाद कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने सोशल मीडिया पर तापसी को कंगना की 'सस्ती कॉपी' कहा था। इसके बाद दोनों अभिनेत्रियों के बीच नेपोटिज्म, फिल्म इंडस्ट्री में बाहरी कलाकारों की स्थिति और बॉलीवुड के कथित 'मूवी माफिया' जैसे मुद्दों को लेकर सार्वजनिक बयानबाजी होती रही। बाद के वर्षों में कंगना ने तापसी और अभिनेत्री स्वरा भास्कर को 'बी-ग्रेड एक्ट्रेस' कहकर भी निशाना बनाया था। इस टिप्पणी के बाद विवाद और गहरा गया था।



नेपोटिज्म से शुरू हुई बहस व्यक्तिगत टकराव तक पहुंची

कंगना और तापसी के बीच विवाद का एक बड़ा हिस्सा बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस से जुड़ा रहा है। कंगना लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में भाई-भतीजावाद और बाहरी कलाकारों के साथ कथित भेदभाव का मुद्दा उठाती रही हैं। वहीं तापसी ने कई मौकों पर कंगना के विचारों और उनके सार्वजनिक बयानों पर अपनी अलग राय रखी है। समय के साथ यह वैचारिक असहमति व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंचती गई। हालांकि दोनों के बीच लगातार कोई सार्वजनिक टकराव नहीं रहा, लेकिन जब भी किसी इंटरव्यू या बयान में एक-दूसरे का जिक्र हुआ, पुराना विवाद फिर सुर्खियों में आ गया।

विश्लेषण: पुरानी लड़ाई का नया दौर क्यों अहम?

इस बार विवाद इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि तापसी का बयान सीधे तौर पर कंगना की कार्यशैली और उनके नजरिए से जुड़ा था, जबकि कंगना की प्रतिक्रिया इससे आगे बढ़कर व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच गई। बॉलीवुड में कलाकारों के बीच वैचारिक मतभेद असामान्य नहीं हैं, लेकिन जब विवाद व्यक्तिगत स्तर तक पहुंचता है तो उसका असर सोशल मीडिया और प्रशंसकों के बीच भी दिखाई देता है। कंगना और तापसी के मामले में यह प्रभाव ज्यादा व्यापक है, क्योंकि दोनों ही लंबे समय से सार्वजनिक रूप से अपने विचार रखने के लिए जानी जाती हैं।



मासिक राशिफल

सितंबर 2026

सितंबर 2026 का महीना कई राशियों के लिए अवसरों, प्रगति और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। इस महीने कार्य, व्यापार, धन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। धैर्य, संकल्प और सकारात्मक सोच से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। जानिए आपकी राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा और किन बातों का रखें विशेष ध्यान।



मेष (Aries)

(21 मार्च - 19 अप्रैल)

इस महीने आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। करियर में प्रगति के योग हैं। धन लाभ के अवसर मिलेंगे।

शुभ रहेगा: करियर, धन, यात्राएँ

सावधानी: क्रोध और जल्दबाजी से बचें।



वृषभ (Taurus)

(20 अप्रैल - 20 मई)

व्यापार में लाभ होगा और आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निवेश सोच-समझकर करें।

शुभ रहेगा: धन, व्यापार, पारिवारिक सुख

सावधानी: अनावश्यक खर्चों से बचें।



मिथुन (Gemini)

(21 मई - 20 जून)

करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है। सामाजिक कार्यों में मान सम्मान मिलेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

शुभ रहेगा: शिक्षा, करियर, संबंध

सावधानी: मन की चंचलता पर नियंत्रण रखें।



कर्क (Cancer)

(21 जून - 22 जुलाई)

मानसिक शांति बनी रहेगी। घर-परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। कार्य क्षेत्र में धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है।

शुभ रहेगा: परिवार, संपत्ति, मित्रता

सावधानी: भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।



सिंह (Leo)

(23 जुलाई - 22 अगस्त)

कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी।

शुभ रहेगा: करियर, मान-सम्मान, धन

सावधानी: अहंकार से बचें, दूसरों की सुनें।



कन्या (Virgo)

(23 अगस्त - 22 सितंबर)

व्यापार में लाभ होगा और अटके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

शुभ रहेगा: नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य

सावधानी: तनाव और थकान से बचें।



तुला (Libra)

(23 सितंबर - 22 अक्टूबर)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा के योग हैं।

शुभ रहेगा: धन, यात्रा, दांपत्य जीवन

सावधानी: फैसले सोच-समझकर लें।



वृश्चिक (Scorpio)

(23 अक्टूबर - 21 नवंबर)

पुराने रुके कार्य पूरे होंगे। आय में वृद्धि के योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सेहत का विशेष ध्यान रखें।

शुभ रहेगा: करियर, धन, प्रतिष्ठा

सावधानी: गुस्से और विवाद से बचें।



धनु (Sagittarius)

(22 नवंबर - 21 दिसंबर)

भाग्य का पुरा साथ मिलेगा। नए अवसर प्राप्त होंगे। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय उत्तम है। यात्रा के योग हैं।

शुभ रहेगा: भाग्य, शिक्षा, यात्रा

सावधानी: लापरवाही से बचें।



मकर (Capricorn)

(22 दिसंबर - 19 जनवरी)

कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा।

शुभ रहेगा: करियर, धन, पारिवारिक सुख

सावधानी: सेहत की अनदेखी न करें।



कुंभ (Aquarius)

(20 जनवरी - 18 फरवरी)

नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय उत्तम है। आर्थिक लाभ होगा। मित्रों और सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

शुभ रहेगा: व्यापार, मित्रता, आय

सावधानी: जल्दबाजी में निर्णय न लें।



मीन (Pisces)

(19 फरवरी - 20 मार्च)

आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

शुभ रहेगा: धन, परिवार, आध्यात्मिकता

सावधानी: खर्चों पर नियंत्रण रखें।

विशेष उपाय

- प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
- शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
- भगवान शिव का जल और वेलपत्र अर्पित करें।
- जरूरतमंदों की सहायता करें, पुण्य प्राप्त होगा।



नोट: यह राशिफल सामान्य फलादेश पर आधारित है। व्यक्तित्व फलादेश के लिए विशेषज्ञ ज्योतिषी से परामर्श लें।

“सकारात्मक सोच और मेहनत, आपके हर लक्ष्य को साकार कर सकती है!”

महत्वपूर्ण तिथियाँ - सितंबर 2026

05 सितंबर - गणेश चतुर्थी
12 सितंबर - एकादशी
17 सितंबर - पूर्णिमा
21 सितंबर - सूर्य संक्रांति
26 सितंबर - प्रदोष व्रत

सितंबर 2026

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



POWERING
A BETTER
TOMORROW

SMARTER POWER. STRONGER TOMORROW.

Advanced Lithium Power Solutions
for Homes, Businesses & Industries.



LOWER COST
Lower running &
maintenance cost



LONGER LIFE
More cycles,
more savings



SILENT OPERATION
No noise.
Just reliable power.



**CLEAN &
SUSTAINABLE**
No emissions
during use



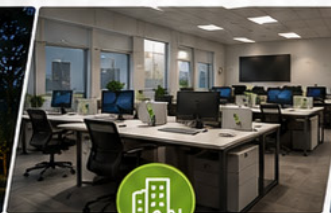
**MINIMAL
MAINTENANCE**
Hassle-free
performance
for years



INTELLIGENT POWER SOLUTIONS FOR EVERY NEED



HOME POWER
Reliable backup for your
home and loved ones.



OFFICE BACKUP
Uninterrupted power for
productivity that never stops.



INDUSTRIAL POWER
Engineered for heavy loads
and critical operations.



SOLAR SOLUTIONS
Store clean energy for a
sustainable tomorrow.



RELIABLE. EFFICIENT. SUSTAINABLE.
**BUILT FOR TODAY.
READY FOR TOMORROW.**



Delivering advanced lithium power solutions
with innovation, quality and trust - to power
progress for a better tomorrow.

 zeltronpower.com

 +91 74288 27714

 care@zeltronpower.com